घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 16- बुधवार 18- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028



मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा,साइबर अपराध और सांस्कृतिक विरासत पर चार नई पहल का प्रस्ताव रखा

ट्रम्प ने मोदी की तारीफ की...कहा-वे टफ इंसान

मनीला,17 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की मंगलवार को फिलीपींस में मुलाकात हुई। दोनों लीडर राजधानी मनीला में हो रही क्वाड मीटिंग में शामिल हुए। ट्रम्प ने मोदी की तारीफ की और कहा कि वे टफ इंसान हैं। क्वाड बैठक में प्रधानमंत्री मोदी,डोनाल्ड ट्रम्प, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए हैं। ट्रम्प ने बैठक के दौरान ईरान पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पागल देश है। इसी वजह से उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा दौर में दुनिया को सबसे अधिक शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता है तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान संवाद,आपसी सम्मान और सहयोग से ही संभव है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा,साइबर अपराध से निपटने,साझा समुद्री विरासत और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के मंच पर चार नई पहलों का प्रस्ताव रखा। मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले,समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को वैश्विक स्तर पर शांति,स्थिरता और पूर्वानुमेयता लाने में योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से दुनिया लगातार एक के बाद एक संकटों का सामना कर रही है। विभिन्न संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने समुद्री व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है।



रेयर अर्थ पर क्वाड देशों के बीच समझौता हुआ

क्वाड देशों के बीच रेयर अर्थ समेत जरूरी खनिजों की सप्लाई बनाए रखने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत चारों देश इन खनिजों को जमीन से निकालने,साफ करने और दोबारा इस्तेमाल करने में एक-दूसरे की मदद करेंगे। इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाएगा और तकनीक भी साझा की जाएगी। इस समझौते का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना है,ताकि अगर चीन इन खनिजों की सप्लाई रोकता है तो दूसरे देशों के उद्योगों पर इसका असर न पड़े। ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका में रेयर अर्थ का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अगले 10 महीनों में इस मामले में चीन की बराबरी कर लेगा।

2027 में मुंबई में पहली क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की बैठक होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 2027 में पहली क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की बैठक मुंबई में होगी। इस फोरम में भारत,अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी,सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मकसद चारों देशों के बीच व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देना है।

पुतिन से मुलाकात पर ट्रम्प बोले... मौका मिला तो जरूर मिलूंगा

ट्रम्प की पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी मुलाकात हो पाएगी या नहीं,लेकिन अगर मौका मिला तो वे जरूर मिलेंगे। ट्रम्प ने बताया कि पुतिन चीन जा रहे हैं और वे भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मेहमान होंगे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रम्प ने कहा कि किम भी वहां आना चाहेंगे,लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है।

मोदी की फिलीपींस यात्रा : भारत-आसियान समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण और मुफ्त ई-वीजा सहित कई पहल की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 16-17 नवंबर की फिलीपींस यात्रा के दौरान भारत-आसियान समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा,परमाणु ऊर्जा,अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज और युवा संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पहल की गई। आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा और नालंदा विश्वविद्यालय में उनके लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी यात्रा के परिणामों की सूची के अनुसार,23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में दीर्घकालिक भारत-आसियान समुद्री सहयोग योजना की घोषणा की गई। इसके तहत संपर्क,वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन,तटरक्षक बलों के बीच सहयोग,समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा के क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने,परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान और भारत-आसियान अंतरिक्ष हैकाथॉन आयोजित करने की भी पहल की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री से की मुलाकात

रणनीतिक साझेदारी को व्यापार,रक्षा एवं सुरक्षा संपर्क और सांस्कृतिक नई गति देने पर की चर्चा



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल से मुलाकात की और उन्हें पदभार संभालने पर व्यक्तिगत रूप से बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने भारत और थाईलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापार,रक्षा एवं सुरक्षा, संपर्क और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई गति देने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत और थाईलैंड समुद्री पड़ोसी हैं और सदियों पुराने साझा इतिहास,संस्कृति तथा आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में नई गति देने के तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह मुलाकात 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रैल 2025 में थाईलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया गया था। बैठक में व्यापार एवं निवेश,रक्षा एवं सुरक्षा, संपर्क,डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी,संस्कृति,पर्यटन और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बिम्सटेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन,मेकांग-गंगा सहयोग और आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय मंचों पर मिलकर काम करने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा भारत-थाईलैंड साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद हटाईं गईं ग्रैप-3 की पाबंदियां



नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी हैं। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, क्षेत्र में ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। आयोग के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 204 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता में सुधार के रुझान को देखते हुए आयोग की ग्रैप उपसमिति ने मौजूदा हालात और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की समीक्षा की। उपसमिति ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों का भी जायजा लिया। अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। इसके बाद 6 नवंबर को लागू किए गए ग्रैप के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया गया। हालांकि,आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के तहत 5 से 20 नवंबर तक लागू कुछ विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसके तहत पूरे एनसीआर में छूट प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली और आसपास के जिलों में राज्य सरकार तथा निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति से कामकाज का निर्देश भी प्रभावी रहेगा। आयोग ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के सभी उपायों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया,नई दरें लागू



नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल गेन्स टैक्स) फिर बढ़ा दिया है। हालांकि,पेट्रोल पर यह शुल्क शून्य ही रखा गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू स्तर पर ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना में बताया कि सरकार ने 16 नवंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया है,जबकि पेट्रोल पर यह शुल्क शून्य रखा गया है। अधिसूचना के मुताबिक विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल शुल्क बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है,जो इससे पिछले पखवाड़े के लिए 11 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर की दर अब बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 11.5 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा कि शुल्क में ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यात को हतोत्साहित कर पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 27 मार्च को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क को लगाया था।

उत्तराखंड में 5 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत,38 घायल

देहरादून/टिहरी/रुद्रप्रयाग,17 नवम्बर 2026। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह तक हुए पांच अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए। सबसे भीषण हादसा टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूलर पुल के पास हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस करीब 120 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में बस चालक समेत नौ लोगों की जान चली गई और 25 यात्री घायल हो गए। इसके आलावा रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में एक बोलेरो वाहन के खाई में गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि टिहरी जिले में तीन अन्य सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की जान चली गई। हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा राहत दलों ने विभिन्न स्थानों पर बचाव अभियान चलाया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर गूलर बस हादसे में घायल यात्रियों का हालचाल जाना और उनके उपचार की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। गूलर पुल के पास बस हादसा पुलिस के अनुसार, विश्वनाथ सेवा की बस मंगलवार तड़के करीब 3:15 बजे हरिद्वार से जोशीमठ के लिए रवाना हुई थी। बस में चालक समेत 34 लोग सवार थे। सुबह करीब 4:50 बजे गूलर पुल के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 120 फीट नीचे गूलर गाड़ में जा गिरी। सूचना मिलते ही मुनिकीरेती और नरेंद्रनगर पुलिस, अग्निशमन विभाग, आपदा राहत दल और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। शिवपुरी स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी बचाव अभियान में सहयोग किया। सभी घायलों को करीब एक घंटे के भीतर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने यात्रियों के सामान को सुरक्षित रखने के लिए गूलर पुलिस चौकी में रखवाया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। गूलर बस हादसे में 25 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। गूलर बस दुर्घटना में मृतकों की पहचान विक्की (37), राज राय (56), बस चालक राजेंद्र सिंह (48), परिचालक अनुज भंडारी (27), पुन्नू (55), सुशील प्रताप सिलोडी (55), दीपक गुप्ता (55), विकास गुप्ता और रोहित कश्यप (35) के रूप में हुई है।

केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार

अवमानना केस में कहा-3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा



नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आप के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। इन सभी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में कोर्ट में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने आप नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। आप नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी केस से हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबर के आधार पर मामला खुद शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा था- जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। मुझे पहले से ही दोषी माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ईडी और सीबीआई के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को सीबीआई ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही हैं। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थीं।

जैव ईंधन से कच्चे तेल आयात पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य,किसान बनेंगे ऊर्जा व हाइड्रोजन उत्पादक : गडकरी

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जैव ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन का विस्तार भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा सालाना 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता समाप्त करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ ऊर्जा,ईंधन,जैव-बिटुमेन और हरित हाइड्रोजन का उत्पादक बनाना होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गडकरी ने मंगलवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन में कहा कि देश में वायु प्रदूषण का करीब 40 फीसदी हिस्सा परिवहन क्षेत्र से आता है।



इससे निपटने के लिए सरकार इथेनॉल,आइसोब्यूटेनॉल,संपीड़ित प्राकृतिक गैस,तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जैव विमानन ईंधन और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दिए जाने के बाद मक्के का बाजार भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के मक्का उत्पादक किसानों को 45 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ हुआ है।

दस साल में मलेरिया और इससे होने वाली मौत के मामलों में करीब 80 प्रतिशत की कमी : राष्ट्रपति मुर्मु

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत ने मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2015 से 2025 के बीच देश में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में करीब 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 155 से घटकर 33 रह गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से 2025 के दौरान देश के 160 जिलों में मलेरिया का एक भी स्थानीय मामला सामने नहीं आया। यह उपलब्धि वैज्ञानिकों,स्वास्थ्य कर्मियों,सरकार और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रपति मंगलवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय



मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कर रही थीं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने संस्थान से जुड़े वर्तमान और पूर्व वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा स्वास्थ्यकर्मियों को 50 वर्षों की वैज्ञानिक सेवा और मलेरिया नियंत्रण में योगदान के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया लंबे समय तक भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में इस बीमारी का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि गांवों में मलेरिया के कारण लोगों की आजीविका, शिक्षा और भविष्य प्रभावित होते देखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों को दवाओं का निर्धारित कोर्स पूरा करने के प्रति जागरूक करना जरूरी है, ताकि बीमारी का प्रभावी उपचार हो और दोबारा संक्रमण का खतरा कम किया जा सके।

राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया के खिलाफ मिली सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता बरतनी होगी। इसके लिए जांच,उपचार और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ मच्छरों पर नियंत्रण, नई दवाओं और टीकों के विकास तथा जनजागरूकता अभियान को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ हर उस गांव और समुदाय तक पहुंचना चाहिए,जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

संपादकीय

राजनीति की केंद्रीय धुरी बनता हिंदुत्व

स्वाधीनता के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक धारा ऐसी रही, जिसका सपना राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व लाना रहा। भाजपा के राष्ट्रीय उभार के बाद यह सपना पूरा हुआ। इसके बावजूद राजनीति का बड़ा हिस्सा अब भी सेक्युलरवादी खोल में अल्पसंख्यकवाद केंद्रित राजनीति ही करता है। इसी कारण सेक्युलरिज्म को छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा मिली। यदि सेक्युलर राजनीति का कोई पैरोकार राम मंदिर जाने की घोषणा करे तो यह मामूली बात नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 12 दिसंबर को राम मंदिर में दर्शन करने जाना राजनीति में आ रहे बदलाव का प्रतीक है। अखिलेश जिस राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी न तो राम मंदिर निर्माण में भागीदारी रही, न ही वह अयोध्या ढांचा ध्वंस को स्वीकार करती है। फिर भी वे राम मंदिर जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अब उन्हें भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए हिंदुत्ववादी राजनीति जरूरी लगने लगी है।आज हिंदुत्व की राजनीति का प्रमुख चेहरा भाजपा है,पर स्वाधीनता के बाद की राजनीति में हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा हिंदू महासभा और स्वामी करपात्री जी की रामराज्य परिषद थी। भाजपा का पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ भी इसी राजनीति की कड़ी रहा। ये दल सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू समाज के अधिकारों, परंपराओं और मान्यताओं की उपेक्षा करने की तत्कालीन राजनीति के विरोधी रहे। हिंदुत्ववादी धारा की राजनीति सेक्युलरिज्म के बहाने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती थी। हालांकि तत्कालीन राजनीति ने तुष्टीकरण के विरोध को अल्पसंख्यक विरोध के रूप में प्रचारित किया। बाद में सेक्युलरवाद ऐसा फैशन बना, जहां हिंदू परंपराओं-मान्यताओं को रूढ़िवादी बताना प्रगतिशीलता मान लिया गया। वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव के बाद मोदी और भाजपा के उभार का बड़ा कारण हिंदुत्व की राजनीति भी रही, पर इसे राजनीति की धुरी मानने से राजनीति के बड़े हिस्से को परहेज रहा। तमाम सेक्युलरवादी दलों को भाजपा का यह उभार तात्कालिक लगा और उन्होंने माना कि यह उभार कुछ ही दिनों का मेहमान है,पर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दें तो भाजपा के नेतृत्व में हिंदुत्व की राजनीति गहरा असर दिखाती रही। इसे रोकने में जब भाजपा विरोधी दल नाकाम रहे तो उन्हें मजबूरी में ही सही, हिंदुत्व का खुले-छिपे रूप में सहारा लेना पड़ा। जैसे 2017 के गुजरात और 2018 के कर्नाटक चुनावों के समय राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिर-मंदिर गए। गुजरात में वे नाकाम रहे, कर्नाटक में कामयाब। इसके बाद राहुल फिर छद्म सेक्युलरवादी धारा की ओर लौट पड़े।

जहरीली हवा,धूम्रपान और घरेलू प्रदूषण बन रहे

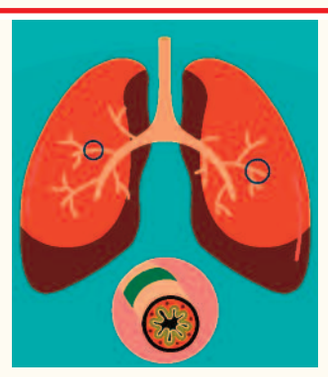
फेफड़ों के दुश्मन,हर सांस पर प्रदूषण का पहरा,कैसे मिले सीओपीडी से मुक्ति?



योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

सांस लेना जीवन की सबसे सहज और स्वाभाविक क्रिया है लेकिन तेजी से बिगड़ते पर्यावरण और बदलती जीवन शैली ने आज इसी सहज प्रक्रिया को चुनौती बना दिया है। महानगरों में जहरीली हवा,घरों के भीतर धुएं का जमाव, तंबाकू का बढ़ता सेवन और कार्य स्थलों पर हानिकारक धूल-कणों का संपर्क धीरे-धीरे हमारे फेफड़ों को कमजोर कर रहा है। इसका एक गंभीर परिणाम 'क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज'(सीओपीडी) के रूप में सामने आ रहा है। यह फेफड़ों की ऐसी दीर्घकालिक बीमारी है,जिसमें सांस की नलियां संकरी हो जाती हैं,उनमें सूजन और बलगम जमा होने लगता है तथा फेफड़ों की वायुकोषिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति को सांस लेने और सामान्य शारीरिक गतिविधियां करने में परेशानी होने लगती है। विडंबना यह है कि इस बीमारी की शुरुआत अक्सर इतनी धीमी होती है कि लोग इसके शुरुआती संकेतों को उम्र का असर,सामान्य खांसी या मौसम का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ष 2023 में दुनियाभर में सीओपीडी के कारण लगभग 34 लाख लोगों की मृत्यु हुई,जो वैश्विक स्तर पर मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण रही। यह आंकड़ा इस बीमारी की गंभीरता और इसके विरुद्ध समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे बुधवार को'विश्व सीओपीडी दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष 18 नवंबर को मनाए जा रहे विश्व सीओपीडी दिवस की थीम है'बेहतर जीवन के लिए शीघ्र निदान और प्रबंधन'।'ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज'(गोल्ड) द्वारा निर्धारित यह विषय स्पष्ट संदेश देता है कि बीमारी की समय रहते पहचान और समुचित उपचार से मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। सीओपीडी के प्रमुख रूपों में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा शामिल हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों की भीतरी परत में लगातार सूजन रहती है और अधिक बलगम बनने लगता है जबकि एम्फीसेमा में फेफड़ों की छोटी-छोटी वायुकोषिकाएं क्षतिग्रस्त होकर अपनी सामान्य लोच खोने लगती हैं। इन दोनों स्थितियों में फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। सीओपीडी के सामान्य लक्षणों में लगातार खांसी,कफ बनना, सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलना,सीने में जकड़न,घरघराहट और असामान्य थकान शामिल हैं। बार-बार सांस संबंधी संक्रमण होना भी खतरे का संकेत हो सकता है। बीमारी बढ़ने पर व्यक्ति को आराम की अवस्था में भी सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सीओपीडी का सबसे प्रमुख जोखिम



कारक धूम्रपान है। सिगरेट,बीड़ी,हुक्का और अन्य तंबाकू उत्पादों का धुआं फेफड़ों की नाजुक संरचनाओं को लगातार नुकसान पहुंचाता है। हालांकि यह मानना गलत है कि केवल धूम्रपान करने वाले ही इस बीमारी की चपेट में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार,निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सीओपीडी के लगभग 30 से 40 प्रतिशत मामले तंबाकू धूम्रपान से जुड़े हैं और घरेलू वायु प्रदूषण भी एक प्रमुख जोखिम कारक है यानी धूम्रपान न करने वाले लोग भी प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने के कारण इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। विशेष रूप से महिलाएं,बच्चे,बुजुर्ग और ऐसे लोग अधिक जोखिम में रहते हैं,जो वर्षों तक लकड़ी,कोयले,उपलों तथा फसल अवशेषों के धुएं के बीच खाना पकाते या काम करते हैं।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस चुनौती को और गंभीर बना देती है। सर्दियों के आगमन के साथ ही यहां वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाता है। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन,निर्माण स्थलों की धूल,से क की धूल,कचरा एवं पराली जलाने से निकलने वाला धुआं और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां मिलकर हवा को जहरीला बना देती हैं। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण विशेषकर पीएम 2.5 इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन तंत्र में सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि प्रदूषण का संकट केवल घर से बाहर तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाला धुआं,अपर्याप्त वेंटिलेशन वाली रसोई,घर के भीतर अगरबत्ती और धूप का अत्यधिक धुआं तथा तंबाकू का निष्क्रिय सेवन भी फेफड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर,खदानों, कारखानों,निर्माण स्थलों,कपड़ा उद्योग और रासायनिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक धूल,धुएं और हानिकारक रसायनों के लगातार संपर्क में रहते हैं। इसलिए सीओपीडी की रोकथाम के लिए केवल सिगरेट छो ने की सलाह पर्याप्त नहीं है बल्कि स्वच्छ घरेलू ईंधन,बेहतर रसोई वेंटिलेशन, कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपकरण और स्वच्छ बाहरी वातावरण भी उतने ही जरूरी हैं।

इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती इसका देर से पहचाना जाना है। बहुत से लोग लंबे समय तक खांसी और सांस फूलने को सामान्य समस्या मानकर स्वयं ही खांसी की दवाएं लेते रहते हैं। कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक क्षमता कम होने को स्वाभाविक समझकर चिकित्सकीय जांच नहीं कराते। सीओपीडी की पुष्टि के लिए स्पाइरोमेट्री नामक सांस की जांच सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को एक उपकरण में जोर से सांस छोड़नी होती है,जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता और वायु प्रवाह में रुकावट का पता चलता है। केवल लक्षणों या छाती के एक्स-रे के आधार पर सीओपीडी की पुष्टि नहीं की जा सकती। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लक्षणों और जोखिम कारकों के आधार पर संदेह होने पर स्पाइरोमेट्री से निदान की पुष्टि करने की सलाह देता है। सीओपीडी का फिलहाल ऐसा कोई उपचार उपलब्ध नहीं है,जिससे फेफड़ों को हुआ नुकसान पूरी तरह समाप्त किया जा सके लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मरीज सामान्य और सक्रिय जीवन नहीं जी सकते। समय पर निदान, नियमित उपचार और जीवनशैली में आवश्यक बदलाव से बीमारी की प्रगति को धीमा करने,लक्षणों को नियंत्रित करने तथा गंभीर स्थितियों से बचने में मदद मिल सकती है। चिकित्सक मरीज की स्थिति के अनुसार ब्रोंकोडाइलेटर और अन्य उपयुक्त इनहेलर दवाएं देते हैं, जो सांस की नलियों को खोलने और सूजन कम करने में सहायक होती हैं। जरूरत पे ने पर ऑक्सीजन थैरेपी और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की भी सलाह दी जा सकती है।

सटीक जनसंख्या आँकड़ों के बिना नीतियों की सफलता अधूरी

जनगणना की गुणवत्ता और नागरिकों का विश्वास लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य शर्त



डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

लोकतंत्र में शासन की सफलता केवल योजनाएँ बनाने और बजट आवंटित करने से सुनिश्चित नहीं होती,बल्कि इस बात से तय होती है कि सरकार की नीतियाँ समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को कितना समझती हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी है,उसमें बच्चों,महिलाओं,बुजुर्गों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी क्या है,कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कितने शहरी क्षेत्रों में, कितने परिवार गरीबी,अशिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं–इन सभी प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर जनगणना से मिलता है। इसलिए जनगणना केवल लोगों की गिनती करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि देश की सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का सबसे व्यापक माध्यम है। भारत जैसे विशाल,विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय समाज में विश्वसनीय जनगणना आँकड़ों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। वर्ष 2011 के बाद प्रस्तावित जनगणना 2027 इसलिए ऐतिहासिक महत्त्व रखती है क्योंकि इसके माध्यम से देश को लंबे अंतराल के बाद नई जनसांख्यिकीय तस्वीर प्राप्त होगी। डिजिटल तकनीक,ऑनलाइन डेटा संग्रह और वास्तविक समय में निगरानी जैसी व्यवस्थाएँ इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल तभी सार्थक होगा,जब आँकड़ों की शुद्धता,निष्पक्षता,पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो। विश्वसनीय जनगणना का पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। भारत में खाद्य सुरक्षा, आवास,स्वास्थ्य,शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अनेक योजनाएँ जनसंख्या संबंधी आँकड़ों पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवासीय आवश्यकताओं का आकलन, सटीक आँकड़े नीति निर्माण की बुनियाद तैयार करते हैं। यदि जनगणना में किसी क्षेत्र की आबादी कम दर्ज होती है,तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में संसाधन नहीं पहुँच पाते। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीबों, प्रवासी श्रमिकों, बेघर लोगों और वंचित समुदायों को उठाना पड़ता है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष संसाधनों का न्यायसंगत वितरण है। सरकार को यह तय करना होता है कि कहाँ नए विद्यालय खोले जाएँ, किन क्षेत्रों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है,कहाँ सड़क,पेयजल और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा किस क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिले। उदाहरण के लिए,तेजी से बढ़ती शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन,आवास और स्वच्छता सुविधाओं की माँग अधिक होती है,जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं,कृषि आधारित आधारभूत संरचना और शिक्षा की विशेष आवश्यकता हो सकती है। जनगणना के विश्वसनीय आँकड़े इन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता करते हैं।

जनगणना का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भी गहरा संबंध है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में जनसंख्या



संबंधी आँकड़ों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या में होने वाले बदलावों को समझे बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन स्थापित करना कठिन है। इसी प्रकार वित्त आयोग को राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण संबंधी सिफारिशें तैयार करने में जनसांख्यिकीय तथ्यों सहित अनेक मानकों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार जनगणना के आँकड़े केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं,बल्कि संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संतुलन के भी आधार हैं।

हालाँकि,विश्वसनीय जनगणना सुनिश्चित करना आसान कार्य नहीं है। भारत की भौगोलिक विविधता,विशाल जनसंख्या, सामाजिक विषमताएँ और तेजी से बदलती जीवनशैली इसके सामने अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या की सही गणना सुनिश्चित करना है। प्रवासी श्रमिक,बेघर नागरिक,घुमंतू समुदाय,दूरदराज के आदिवासी समूह और अस्थायी रूप से रहने वाले लोग अक्सर गणना की प्रक्रिया से छूट सकते हैं। महानगरों में काम की तलाश में आने वाले श्रमिकों का निवास अस्थायी होता है। ऐसे लोगों की सही गणना और उपयुक्त स्थान पर उनका पंजीकरण एक जटिल प्रशासनिक चुनौती है। यदि ये समूह आँकड़ों से बाहर रह जाते हैं,तो उनकी वास्तविक समस्याएँ भी नीतिगत प्राथमिकताओं में पीछे छूट सकती हैं। दूसरी चुनौती डिजिटल असमानता है। जनगणना में मोबाइल एप्लीकेशन,डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन निगरानी का उपयोग प्रक्रिया को तेज तथा व्यवस्थित बना सकता है,लेकिन देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति, तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता और डिजिटल साक्षरता का अभाव दूरस्थ ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त,तकनीकी प्रणाली में गड़बड़ी या डेटा अपलोड करने में त्रुटि भी आँकड़ों की गुणवत्ता प्रभावित कर सकती है।

तीसरी चुनौती मानवीय और प्रशासनिक त्रुटियों से जुड़ी है। जनगणना का बड़ा हिस्सा गणनाकर्मियों द्वारा घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने पर आधारित होता है। यदि गणनाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले या प्रश्नों की व्याख्या में एकरूपता न हो,तो गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। कई बार उत्तरदाता भी सामाजिक संकोच जानकारी के अभाव अथवा सरकारी लाभ प्रभावित होने की आशंका के कारण सही जानकारी देने से बचते हैं। भाषा,स्थानीय बोलियों और सामाजिक परिस्थितियों की विविधता इस समस्या को और जटिल बनाती है। इसके साथ ही निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का प्रश्न भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डिजिटल युग में नागरिकों के मन में यह आशंका हो सकती है कि उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। यदि लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि उनकी जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रहेगी,तो वे जनगणना में सहयोग करने से हिचक सकते हैं। इसलिए डेटा सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं,बल्कि जनगणना की विश्वसनीयता से जुड़ा सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रश्न भी है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सबसे पहले गणनाकर्मियों का व्यापक और व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्हें स्थानीय भाषा, सामाजिक संरचना,प्रश्नावली और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। दूसरा,वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि डेटा संग्रह के दौरान ही असामान्य प्रविष्टियों,दोहराव और संभावित त्रुटियों की पहचान हो सके। तीसरा,स्वतंत्र सत्यापन और नमूना आधारित पुनः जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए,जिससे आँकड़ों की गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त,डिजिटल माध्यमों के साथ पारंपरिक गणना विकल्प भी उपलब्ध रहने चाहिए,ताकि तकनीकी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों की आबादी छूटने न पाए। प्रवासी श्रमिकों,बेघर नागरिकों,घुमंतू समुदायों और दूरस्थ बस्तियों तक पहुँचने के लिए विशेष रणनीति बनाई जानी चाहिए। जनगणना के उद्देश्य,प्रक्रिया और गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के बारे में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है। नागरिकों को यह समझाना होगा कि सही जानकारी देना उनके अपने अधिकारों और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

अंततः,जनगणना की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने लोगों की गणना हुई,बल्कि इससे तय होनी चाहिए कि प्राप्त आँकड़े देश की वास्तविक सामाजिक तस्वीर को कितनी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। विश्वसनीय आँकड़े सरकार को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं,जबकि गलत आँकड़े अच्छी नीतियों को भी गलत दिशा में ले जा सकते हैं।

नीली छतरी



गरिमा राकेश गौतम
बाड़मेर,राजस्थान

नीली छतरी वाले
चंद्र की कलाओं से
निर्धारित होता है
ज्योतिषी का पंचाग
जिसके तहत ही
घटती बढ़ती रहती है
तिथियाँ और मनाये जाते है
त्योहार ईद या करवा चौथ
लेकिन इन तिथियों से इतर
होता है मन का पंचाग
जिसकी तिथियाँ चंद्र से नही
मन के चंद्र से निर्धारित होती है
मन से निर्धारित तिथियाँ ही
उल्लास,उमंग,आनंद ,खुशी
,सुख और शांति से भरती है
नीली छतरी वाले चंद्र से इतर
ये अंतर्मन को प्रकाशित करती है ।

अयोध्या के बाद मथुरा पर नजर

भाजपा की रणनीति या चुनावी मजबूरी
अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने 2027 की लड़ाई का बिगुल मथुरा से फूंका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। यह महज एक चिंतन बैठक नहीं,बल्कि उस राजनीतिक रणनीति का संकेत है जिसमें आस्था, जातीय समीकरण,संगठन और सत्ता की ताकत को एक साथ साधने की तैयारी है। सवाल यह है कि भाजपा मथुरा से विपक्ष को घेरना चाहती है या अपनी सरकार के सामने खड़े होते सवालों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है? 16 और 17 नवंबर को मथुरा में हुई भाजपा की बैठक का समय और स्थान दोनों राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,दोनों उपमुख्यमंत्री,प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बताती है कि पार्टी 2027 को हल्के में नहीं ले रही। बैठक में कमजोर बूथों, नाराज कार्यकर्ताओं,संगठन और सरकार के बीच तालमेल तथा विपक्ष के पीडीए समीकरण की काट पर चर्चा की खबरें हैं। यानी भाजपा के भीतर भी यह एहसास है कि सत्ता में होना और चुनाव जीतना दो अलग-अलग बातें हैं। अगर सब कुछ उसके पक्ष में होता तो चुनाव से पहले संगठन को इतनी गंभीरता से दुरुस्त करने की जरूरत क्यों पड़ती? मथुरा की जमीन से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया 'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी।' यह नारा राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर कई सवाल छिपे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में किसी भी पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर जाकर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। मंदिर निर्माण की बात करना राजनीतिक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले उसे चुनावी विजय की तरह पेश करना संवैधानिक मर्यादा को कमजोर करता है। आस्था का सम्मान जरूरी है, मगर आस्था के नाम पर कानून को चुनावी मंच की सीढ़ी नहीं बनाया जा सकता। भाजपा की रणनीति साफ दिखाई देती है। अयोध्या का मुद्दा उसके लिए बड़ी राजनीतिक पूंजी बना। अब मथुरा के जरिए वह हिंदुत्व के भावनात्मक विस्तार की संभावना तलाश रही है। लेकिन क्या हर चुनाव में नया धार्मिक प्रतीक खड़ा करना ही विकास का विकल्प है? जनता को रोजगार,महंगाई,किसानों की आय, शिक्षा,स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जवाब चाहिए। मंदिर की चर्चा इन सवालों को हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। चुनावी मंच पर जयकारे गूंज सकते हैं,लेकिन घर का बजट बिगड़ने पर मतदाता का सवाल भी उतनी ही ताकत से उठता है। भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ धार्मिक मुद्दे की नहीं,अखिलेश यादव की राजनीति की भी है। अखिलेश खुद को यदुवंशी बताते हैं और कृष्ण के प्रतीक को अपनी राजनीतिक पहचान से जोड़ते रहे हैं। महाभारत के रूपकों,सारथी की छवि और पीडीए की राजनीति के जरिए वह भाजपा के सामने वैचारिक चुनौती पेश करना चाहते हैं।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

जितनी उन्नत टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा धोखाधड़ी की आशंकाएं

संदर्भ भारत की जनसंख्या



संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

तकनीक तेजी से आगे बढ़ी,लेकिन आम आदमी की समझ अब भी काफी पीछे है। विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के जीवन को बहुत तेजी से बदल दिया है। इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल बैंकिंग और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में समेट दिया है। आज घर बैठे बैंक का काम हो सकता है,हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात की जा सकती है और कुछ ही सेकंड में दुनिया भर की जानकारी मिल सकती है। लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ एक बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी की समझ भी तकनीक के साथ उतनी ही तेजी से बढ़ी है? खासकर भारत जैसे विकासशील देश में जहां की जनसंख्या इतनी विशाल है एवं इसका बड़ा प्रतिशत गांव में निवास करता है जिम तकनीकी ज्ञान की जानकारी की संभावनाएं अत्यंत कम है। इसका जवाब बहुत संतोषजनक नहीं है।आज मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है,लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी जनसंख्या के बड़े प्रतिशत को नहीं है। यही कमी धोखेबाजों के लिए सबसे बड़ा मौका बन रही है। अधूरी जानकारी, जल्दबाजी,लालच और दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा लोगों को आर्थिक नुकसान की ओर धकेल रहा है। कई बार लोगों को अपनी गलती का पता तब चलता है,जब उनके बैंक खाते से जीवनभर की कमाई निकल चुकी होती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़े इस खतरे की गंभीरता बताते हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर आर्थिक धोखाधड़ी की लगभग 24.02 लाख शिकायतें दर्ज हुईं और करीब 22,495 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की सूचना दी गई। वर्ष 2021 में यह रकम लगभग 551 करोड़ रुपये थी। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी का खतरा भी कितना बढ़ गया है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब धोखाधड़ी के तरीके भी बदल गए हैं। पहले कोई व्यक्ति फोन करके बैंक अधिकारी बनता था और लोगों से ओटीपी या बैंक की जानकारी मांगता था। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी परिचित व्यक्ति की आवाज की नकल की जा सकती है। किसी अधिकारी या बड़े व्यक्ति का नकली वीडियो बनाया जा सकता है। तस्वीर और आवाज इतनी असली लग



सकती हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए सच और झूठ में अंतर करना मुश्किल हो जाए। इस तरह की नकली तस्वीरों और वीडियो को डीपफेक कहा जाता है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया ने भी नवंबर 2024 में इस तरह के खतरों को लेकर चेतावनी दी थी।

जरा सोचिए,किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास उसके बेटे की आवाज में फोन आता है कि वह किसी मुसीबत में फंस गया है और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। आवाज बेटे जैसी है, बात करने का तरीका भी वैसा ही है और परेशानी की बात सुनकर माता-पिता घबरा जाते हैं। वे बिना जांच किए पैसे भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि फोन करने वाला उनका बेटा नहीं, बल्कि कोई धोखेबाज था। इसी तरह कुछ लोग पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वे लोगों को डराते हैं कि उनके नाम से कोई अपराध हुआ है और उन्हें घर में ही जांच पूरी होने तक नजरबंद रहना होगा। इस डर से कई लोग अपनी जमा पूंजी तक दे देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को इस तरह घर में बंद रहने का आदेश नहीं दे सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल केवल बैंक खातों से पैसे निकालने तक सीमित नहीं है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी,नकली निवेश योजनाएँ,ऑनलाइन सामान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी,फर्जी सरकारी योजनाएँ,मोबाइल एप के माध्यम से ठगी और सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल करना भी इसके उदाहरण हैं। अब धोखेबाजों के लिए अच्छी भाषा में संदेश लिखना,नकली वेबसाइट बनाना और लोगों को अपनी बातों में फंसाना पहले से कहीं आसान हो गया है। इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी मदद कर रहा है।भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग और आर्थिक लेन-देन में इस तरह की धोखाधड़ी के खतरों को लेकर चिंता जताई है। नकली आवाज, वीडियो और संदेश के जरिए लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साफ है कि आने वाले समय में केवल बैंक और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना पर्याप्त नहीं होगा। आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या डिजिटल इंडिया का अर्थ केवल हर हाथ में मोबाइल और हर व्यक्ति के बैंक खाते तक इंटरनेट की सुविधा पहुँचाना है? क्या मोबाइल चलाना और ऑनलाइन पैसे भेज देना ही डिजिटल ज्ञान है? वास्तव में डिजिटल ज्ञान का अर्थ यह भी है कि हम सही और गलत संदेश में अंतर कर सकें, किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें और अपनी निजी तथा बैंक संबंधी जानकारी को सुरक्षित रखना जानें।

गाँवों,छोटे शहरों और बुजुर्गों के सामने यह समस्या और भी गंभीर है। बहुत से लोग मोबाइल का उपयोग तो करते हैं,लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि किसी को ओटीपी बताने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अनजान लिंक खोलने, किसी के कहने पर नया एप डाउनलोड करने या मोबाइल की स्क्रीन दूसरे व्यक्ति को दिखाने से भी धोखाधड़ी हो सकती है। कई लोग यह भी नहीं जानते कि पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। क्यूआर कोड स्कैन करने और पिन डालने के मामले में भी सावधानी जरूरी है। इस समस्या का समाधान मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाना नहीं,बल्कि उनका सही इस्तेमाल सीखना है। हर व्यक्ति को कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिए। अपना ओटीपी,बैंक का पासवर्ड और यूपीआई पिन किसी को न बताएं। बैंक का अधिकारी बनकर फोन करने वाले व्यक्ति पर भरोसा न करें। कोई परिचित अपनी आवाज में पैसे मांगे तो उसके पुराने मोबाइल नंबर पर फोन करके पहले पुष्टि कर लें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी योजना में बि

राजेश देवांगन ने संभाला एएसपी का पदभार,9 थानों की मिली जिम्मेदारी

डीआईजी एवं एसएसपी ने सौंपी प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की कमान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी राजेश देवांगन ने मंगलवार को सरगुजा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने उन्हें जिले के महत्वपूर्ण थानों,चौकियों और पुलिस शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी है।



शासन के आदेश के तहत देवांगन का स्थानांतरण सरगुजा किया गया है। इससे पहले वे रायपुर में नगर पुलिस अधीक्षक और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में एसडीओपी के पद पर पदस्थ थे। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें अंबिकापुर,गांधीनगर,मणिपुर, लखनपुर,उदयपुर और दरिमा थानों के साथ होलीक्रॉस अस्पताल चौकी,कुन्नी और केदमा चौकी का पर्यवेक्षण सौंपा गया है। इसके अलावा रक्षित केंद्र अंबिकापुर,महिला थाना,महिला सेल और शहीद सेल का प्रभार भी दिया गया है। वे पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य प्रशासनिक एवं विभागीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

बालिकाओं के स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को नई उड़ान...कोरवापारा स्कूल में बने अत्याधुनिक बालिका शौचालय का हुआ लोकार्पण

-संवाददाता-
बलरामपुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



राज्य के ग्रामीण अंचल में शिक्षा और स्वच्छता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बैढी के पूर्व माध्यमिक शाला कोरवापारा में सोमवार को बालिका शौचालय का औपचारिक लोकार्पण किया गया। खास बात यह रही कि इस शौचालय का फीता किसी अधिकारी या अतिथि ने नहीं,बल्कि विद्यालय की नन्हीं छात्राओं ने अपने हाथों से काटकर किया। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष विनय भगत रहे। इस पहल से स्कूल की छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला,जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता (हाइजीन) को लेकर बढ़ती जागरूकता का स्पष्ट संदेश गया।

'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार' मिशन के तहत हो रहा निर्माण : कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में, जनपद पंचायत राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण'योजना के तहत कुल 43 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। कोरवापारा स्कूल में हुआ यह लोकार्पण इसी अभियान की एक अहम कड़ी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्कूलों में बालिकाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां : कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने 'VB-G RAM G' योजना और स्वच्छता के महत्व को दर्शाते हुए एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित अतिथियों और ग्रामीणों ने खूब सराहा। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य रूप से:

- जनपद सदस्य श्रीमती सुंदरमुनि मिंज
- जनपद पंचायत सीईओ संजय दुबे
- सरपंच ईसु कुजूर
- प्रधान पाठक श्याम सुंदर चौरगे

इनके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे,ग्रामीणजन, क्षेत्र के पंचगण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मामलों के त्वरित निराकरण हेतु 21 नवम्बर 2026 को विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 21 नवम्बर 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दर्ज चेक अनादरण (चेक बाउंस) के प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है।

वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा पर बरसे कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत

आधी रात सीतापुर में जनसभा,मैनपाट के पैगा में ग्रामीणों से कुड़ुख भाषा में किया संवाद,आज हसदेव व तारा कोल ब्लॉक प्रभावितों से करेंगे मुलाकात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार की देर रात सरगुजा पहुंचे। उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी जरीता लैतफलांग भी मौजूद थीं। जशपुर से रात करीब 12.30 बजे सीतापुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव,पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीतापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुखदेव भगत ने वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने जल,जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद वे मैनपाट के ग्राम पैगा पहुंचे, जहां ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कुड़ुख भाषा में संवाद भी किया। पैगा में उन्होंने बॉक्साइट खनन से प्रभावित लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

आज कोल ब्लॉक प्रभावितों से करेंगे संवाद : दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को सुखदेव भगत उदयपुर विकासखंड के ग्राम साल्ही और कांटारोली पहुंचेंगे। यहां वे हसदेव और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। ग्राम कांटारोली में कांग्रेस की जनसभा भी आयोजित की गई है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

आज जिला कांग्रेस कार्यालय में लेंगे बैठक

आज सुखदेव भगत अंबिकापुर पहुंचेंगे। यहां जिला कांग्रेस कार्यालय में अंबिकापुर,सीतापुर और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें हार गई थी। अब आगामी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों को लेकर सक्रियता बढ़ाने में जुटी है। सरगुजा में सड़क,खनन और आदिवासी हितों से जुड़े मुद्दे कांग्रेस के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से 02 से 17 नवंबर 2026 के मध्य संस्था स्तर, विधानसभा स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में 17 नवम्बर को विधानसभा से चयनित शीर्ष 10-10 छात्र-छात्राओं के मध्य संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर में जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका निरीक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष कुमार देवांगन द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी एवं विद्यार्थियों से यह भी अपील किया कि ऐसे छूटे हुए विद्यार्थी जो 17 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे भावी मतदाता के रुप में अग्रिम आवेदन कर सकते है तथा उनके घर या आसपास के जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र विद्यार्थी युवा हो उनका भी नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन ECINET एप के माध्यम से स्वयं एवं ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से फार्म 06 लेकर भरा जाए। जिला परियोजना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (स्वीप).श्री गिरीश गुप्ता ने यह जानकारी दिया की विधानसभा स्तर से दोनो विधा में कुल 60 (30-30) विद्यार्थी चयनित होकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए है,जिसमें जिला स्तर से चयनित शीर्ष 10-10 छात्र-छात्राओं की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगी। साथ ही आयोग द्वारा निर्धारित निबंध प्रतियोगिता का विषय 'मतदान का महत्व' तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विषय 'मतदाता सूची तैयार करना, EVM एवं VVPAT, मतदान प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया' रखा गया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक की जागरुकता और मतदान में सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है।

लोन क्लोज कराने के नाम पर सरकारी कर्मचारी दंपती से 6.10 लाख की ठगी

बैंक और फाइनेंस कंपनी में कर्ज जमा कराने का दिया था झांसा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बैंक और फाइनेंस कंपनी का लोन क्लोज कराने का झांसा देकर एक युवक ने सरकारी कर्मचारी दंपती से 6 लाख 10 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी ने रकम लेने के बाद दोनों लोन सेटल होने की बात कही, लेकिन बैंकों में पैसे जमा नहीं किए। शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पटपरिया निवासी शकुंतला टोप्पो ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके पति इग्नासियुस टोप्पो ने वर्ष 2023 में एक्सिस बैंक से 5.50 लाख और चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से 7.64 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। लोन की पूरी किस्तें जमा नहीं होने से ब्याज बढ़ रहा था। इसी दौरान पति के परिचित प्रतीक ठाकुर ने 13 मार्च 2025 को उनके घर पहुंचकर दोनों लोन की रकम जमा कराने का भरोसा दिया। पुरानी पहचान के कारण दंपती ने उस पर विश्वास कर लिया और उसी दिन दो लाख रुपए नकद दे दिए। इसके बाद 7 जुलाई 2025 तक किश्तों में 4.10 लाख रुपए ऑनलाइन और चेक के माध्यम से दिए। इस तरह आरोपी को कुल 6.10 लाख रुपए सौंपे गए। रकम लेने के बाद प्रतीक ठाकुर ने दोनों वित्तीय संस्थानों का लोन सेटल होने की बात कही, लेकिन कोई रसीद नहीं दी। दंपती के पूछने पर वह लगातार बहाने बनाता रहा। कुछ दिन पहले चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से इग्नासियुस टोप्पो के पास लोन की बकाया राशि जमा करने के लिए फोन आया।

राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन आज

विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित,सांसद श्री चिंतामणी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले में 18 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थानीय राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम हॉल अंबिकापुर में दोपहर 12:00 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणी महाराज शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लुण्ड्रा विधानसभा श्री प्रबोध मिंज करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सीतापुर विधायक श्री राम कुमार टोप्पो,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर,सरगुजा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देव नारायण यादव, अम्बिकापुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत एवं नगर पालिक निगम के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण- समारोह के दौरान कई प्रमुख सांस्कृतिक एवं सम्मान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जनजातीय शहीद परिवारों एवं



समाज प्रमुखों का विशेष सम्मान किया जाएगा। जिला स्तरीय जनजातीय विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी,जिसमें क्राफ्ट,कला, शिल्प,पारंपरिक व्यंजन, वाद्य यंत्र, रंग,शौर्य,औषधी और पुस्तक मेले का प्रदर्शन होगा। लोक नृत्य कलाकारों तथा चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। समारोह में आकर्षक लोक नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

97 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

मेडिकल दुकान से इंजेक्शन लाकर स्थानीय स्तर पर बेचने की थी तैयारी,97 हजार रुपए का माल जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 97 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं,जिनकी कीमत करीब 97 हजार रुपए बताई गई है। आरोपी मेडिकल दुकान से इंजेक्शन लाकर स्थानीय स्तर पर बिक्री करने की तैयारी में थे। पुलिस के अनुसार,16 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डिगमा निवासी अंकित गुप्ता अपने साथी साहिद अंसारी के साथ शंकरघाट खनिज बैरियर के पास नशीले इंजेक्शन बेचने आने वाला है। सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 40 नग बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन (रेक्सोजेसिक) और 57 नग फेनिरामाइन मैलेट इंजेक्शन (एविल) बरामद किए गए। जब्त इंजेक्शनों की कुल मात्रा 650 एमएल और कीमत करीब 97 हजार रुपए बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने मेडिकल दुकान से इंजेक्शन लाकर बिक्री करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी अंकित गुप्ता (27), निवासी जयसिंहनगर,जिला शहडोल (मप्र), हाल मुकाम डिगमा,गांधीनगर और साहिद अंसारी (25), निवासी दिनाबार,जिला पलामू (झारखंड) के खिलाफ कोतवाली थाने में,धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा,अनुराग वर्मा,एएसआई देवनारायण यादव सहित आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा, हिमांशु दास,लालबाबू सिंह और शिव राजवाड़े शामिल रहे।

संविदा पदों की भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)'(VB- G RAM G) के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर और लेखापाल के रिक्त संविदा पदों की भर्ती के संबंध में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। आवेदनों के प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची का प्रकाशन कर 10 नवंबर 2026 तक दावा/आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि तक दोनों पदों के लिए कुल 06 दावा/आपत्तियां प्राप्त हुईं। जिसमें सहायक प्रोग्रामर (संविदा) कुल 03 दावा/आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 01 को मान्य तथा 02 को अमान्य एवं लेखापाल (संविदा) कुल 03 दावा/आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 01 को मान्य तथा 02 को अमान्य किया गया।

कुल प्राप्त 06 दावा/आपत्तियों में से 02 को मान्य तथा 04 को अमान्य करते हुए निराकरण का प्रकाशन कर दिया गया है। दावा/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अब पदवार पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) का भी प्रकाशन कर दिया गया है।

सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in तथा सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

आपराधिक मामलों में घिरे तीन शिक्षकों को विभागीय संरक्षण देने का आरोप,कलेक्टर से शिकायत

91 दिन से लेकर 73 और 37 दिन तक जेल में रहे शिक्षक,एक शिक्षक को पांच साल की सजा,विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।





सरगुजा जिले में आपराधिक मामलों में संलिप्त शासकीय शिक्षकों को विभागीय संरक्षण देने का मामला सामने आया है। उदयपुर विकासखंड के दो प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परवेज आलम ने कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायत में तत्कालीन एवं वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले में विभागीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्टर को 6 नवंबर 2026 को सौंपे गए शिकायत पत्र के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला पेंडरखी के प्रधान पाठक विजय कुमार यादव वर्ष 2019 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार हुए थे।

वे 91 दिन न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहे और बाद में जमानत पर रिहा हुए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर और जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की। उनकी सेवा पुस्तिका में भी इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। आरोप है कि आपराधिक प्रकरण लंबित रहने के दौरान विजय यादव को स्वच्छ एवं पदोन्नति योग्य वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का लाभ देते हुए माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत कर दिया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि विजय यादव को बाद में पांच वर्ष के कारावास की सजा हुई और जनवरी 2026 से वे जेल में निरुद्ध हैं। उनकी पत्नी मीना यादव ने 11 अगस्त 2026 को इसकी सूचना विकासखंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर को दी थी। इसके बावजूद सूचना जिला शिक्षा अधिकारी तक भेजने में एक सप्ताह से अधिक का समय लगा। शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना मिलने के बाद भी 22 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं।

इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला कटकोनिया पारा के प्रधान पाठक राजकुमार टोप्पो 73 दिन और शासकीय प्राथमिक शाला जरहाडीह के सहायक शिक्षक त्रिपाल टोप्पो 37 दिन तक जेल में निरुद्ध रहे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन शिक्षकों की अनुपस्थिति के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होने के बावजूद जेल में निरुद्ध शिक्षकों की अनुपस्थिति का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के 15 सितंबर 1977 के परिपत्र का हवाला देते हुए दोषसिद्ध लोक सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों से शासन को हुए वित्तीय नुकसान की वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, तत्कालीन एवं वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर तथा तत्कालीन एवं वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है।

गौ अष्टमी पर गौ आश्रय धाम में उमड़ी श्रद्धा, विधि-विधान से हुआ गौ माता का पूजन

सैकड़ों गौ प्रेमियों ने की पूजा-अर्चना,गौवंशों को खिलाया आहार;30 हजार से अधिक गायों के रेस्क्यू का दावा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



गौ अष्टमी का पर्व सरगुजा जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खलीबा स्थित गौ आश्रय धाम में सैकड़ों की संख्या में गौ प्रेमी पहुंचे। यहां विधि-विधान से गौ माता की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की गई।

साथ ही गौवंशों को आहार खिलाकर सेवा और संरक्षण का संदेश दिया गया। गौ अष्टमी पर सुबह से ही गौ आश्रय धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गौ माता का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान गौ सेवा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया।गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष रिंकू तिवारी ने बताया कि गौ आश्रय धाम पिछले कई वर्षों से बेसहारा और जरूरतमंद गौवंशों की सेवा एवं संरक्षण में जुटा हुआ है। संस्था के अनुसार,अब तक सरगुजा जिले में 30 हजार से अधिक गायों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस अवसर पर गौ आश्रय धाम में भंडारे का आयोजन भी किया गया।

इसमें बड़ी संख्या में पहुंचे गौ प्रेमियों और पशु प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में शामिल सरोज मिश्रा ने भी गौ माता का पूजन कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। गौ अष्टमी का आयोजन धार्मिक आस्था के साथ ही गौवंशों के प्रति संवेदना, सेवा और संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का संदेश देता नजर आया।

CMYK



नई धान खरीदी शुरू...पुराने घोटालों पर खामोशी!

क्या दागदार व्यवस्था को ही मिल गया नया जीवन?

केंद्रों में कलेक्टर का निरीक्षण,लेकिन पुरानी अनियमितताओं पर कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?

- पुरानी गड़बड़ियों पर पर्दा,नई खरीदी में पारदर्शिता का दावा! सूरजपुर की धान खरीदी पर बड़े सवाल...
- सत्र बदला,खरीदी शुरू हुई,लेकिन व्यवस्था नहीं बदली! पुराने घोटालों पर जवाबदेही गायब...
- धान खरीदी में किसानों को सुविधा का भरोसा,मगर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई का पता नहीं!
- नई खरीदी के लिए प्रशासन मुस्तैद,पुराने घोटालों पर जिम्मेदार अब भी बेफिक्र?
- निरीक्षण और निर्देशों से कितनी बदलेगी व्यवस्था? पुराने धान घोटालों का हिसाब अब भी बाकी
- किसानों की सुविधा पर जोर,लेकिन पिछली अनियमितताओं पर मौन! पारदर्शिता के दावों की असली परीक्षा

- क्या पुरानी गड़बड़ियों को भुलाकर शुरू कर दी गई नई धान खरीदी? जवाबदेही पर प्रशासन मौन
- केंद्रों में कलेक्टर का निरीक्षण,किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के निर्देशों की गूंज...
- लेकिन पिछले सत्र की गड़बड़ियों,शिकायतों और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का सवाल अब भी अनुत्तरित
- कलेक्टर ने तीन खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर दिया पारदर्शी खरीदी का निर्देश...
- 60 केंद्रों में 68,531 किसानों से होगी खरीदी,लेकिन पिछले सत्र की शिकायतों,जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का ब्यौरा अब भी सार्वजनिक नहीं।

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है,खरीदी शुरू होते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय दिखाई देने लगा है, कलेक्टर रेना जमील धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं,अधिकारियों को किसानों की सुविधा,पर्याप्त बारदाना,हमाल,तौल व्यवस्था, नमी की जांच,सीसीटीवी कैमरे और पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं,अवैध धान परिवहन और भंडारण रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं तथा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं,प्रशासन की ओर से इस बार खरीदी व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम तैयारियों और दावों के बीच एक बड़ा सवाल जिले की धान खरीदी व्यवस्था का पीछा नहीं छोड़ रहा है,आखिर पिछले खरीदी सत्र में सामने आई अनियमित ताओं का क्या हुआ? जिन शिकायतों ने सहकारी समितियों और धान खरीदी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, उनकी जांच कहां तक पहुंची? जिन कर्मचारियों और जिम्मेदारों पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या विभाग ने पिछली गड़बड़ियों से कोई सबक लिया या फिर पुराने सवालों को पीछे छोड़कर नई खरीदी शुरू कर देना ही पर्याप्त मान लिया गया? विडंबना देखिए कि नई खरीदी के पहले किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी,लेकिन पिछले सत्र की व्यवस्था से जुड़े सवालों पर अब भी स्पष्ट जवाब सामने नहीं है, किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के नाम पर निरीक्षणों का दौर शुरू हो गया है,मगर पुरानी अनियमितताओं की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी,यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है, यदि पिछली गड़बड़ियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई,तो नई खरीदी में पारदर्शिता के दावों पर किसानों का भरोसा कैसे मजबूत होगा?

निरीक्षण में नमी मापी मशीन से लेकर बोरियों के वजन तक की जांच-कलेक्टर रेना जमील ने 17 नवंबर को धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने कृष्णपुर देवनगर और चंदरपुर धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, केंद्रों में पेयजल,बैठने और छांव की व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना,हमाल तथा तौल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखने पर जोर दिया गया,कलेक्टर ने खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जांच कराई गई और कलेक्टर ने स्वयं भी मशीन से नमी मापकर व्यवस्था का परीक्षण किया,धान की बोरियों का वजन कराकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदी करने को कहा गया, मिलर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली खराब बोरियों को स्वीकार नहीं करने, केंद्रों में साफ-सफाई बनाए रखने, सीसीटीवी कैमरे चालू रखने तथा ऋण सूची और आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए,ये निर्देश खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं,लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार निरीक्षण का दायरा केवल मौजूदा सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं तक सीमित रहेगा या फिर पिछले वर्षों में सामने आई अनियमितताओं की समीक्षा भी इसी गंभीरता से की जाएगी? क्योंकि धान खरीदी में पारदर्शिता केवल नमी मापने,तौल कराने और सीसीटीवी लगाने से नहीं आती,पारदर्शिता तब स्थापित होती है,जब रिकॉर्ड, पंजीयन,खरीदी,भुगतान, भंडारण और परिवहन की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह हो तथा किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।

अवैध धान परिवहन रोकने चार चेक पोस्ट,नौ तहसीलों में उड़नदस्ता दल-जिले में अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासन ने चार चेक पोस्ट स्थापित किए हैं, यहां अलग-अलग पालियों में निगरानी की जाएगी, इसके अतिरिक्त जिले की सभी नौ तहसीलों में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं, प्रशासन ने कोचियों-बिचौलियों तथा अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर विशेष नजर रखने की बात कही है, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है, अवैध धान परिवहन पर निगरानी जरूरी है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचना चाहिए,लेकिन निगरानी की यह सख्ती केवल चेक पोस्ट और सड़कों पर चलने वाले वाहनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,खरीदी केंद्रों के भीतर होने वाली प्रक्रिया पर भी उतनी ही गंभीरता से नजर रखना आवश्यक है,अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय है,लेकिन खरीदी केंद्रों के भीतर रिकॉर्ड में गड़बड़ी,पंजीयन संबंधी अनियमितता,तौल में अंतर,भंडारण और उठाव से जुड़े मामलों की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है,यदि किसी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसकी जांच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए और जांच के परिणाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

पुरानी व्यवस्था पर उठे सवालों को आखिर कब मिलेगा जवाब?-सूरजपुर जिले में धान खरीदी को लेकर पिछले सत्रों में सामने आई शिकायतों और अनियमितताओं ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे,इन सवालों को नजरअंदाज करके केवल नए सत्र की तैयारियों में जुट जाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,नई खरीदी शुरू हो गई है,लेकिन पुरानी शिकायतों की स्थिति और उन पर हुई कार्रवाई का स्पष्ट ब्यौरा सामने आना भी उतना ही जरूरी है,प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले खरीदी सत्र में जिन केंद्रों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, वहां क्या जांच कराई गई? जांच में क्या तथ्य मिले? जिन कर्मचारियों या पदाधिकारियों पर आरोप लगे थे,उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्रवाई हुई? क्या किसी मामले में वसूली या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई? क्या जांच लंबित है और यदि लंबित है तो उसका कारण क्या है? यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने के लिए नहीं,बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए हैं,किसी पर आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं,लेकिन शिकायतों की जांच न होना या जांच के परिणाम सार्वजनिक नहीं करना भी व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर करता है,प्रशासन का दायित्व है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए और जो भी तथ्य सामने आएं,उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करे।

नई खरीदी का भरोसा पुराने मामलों की जवाबदेही से ही मजबूत होगा-धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है, किसानों के लिए यह केवल सरकारी खरीदी की प्रक्रिया नहीं,बल्कि सालभर की मेहनत का प्रतिफल है,ऐसे में खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, कलेक्टर का केंद्रों का निरीक्षण करना,किसानों से बातचीत करना,नमी और वजन की जांच करना तथा अधिकारियों को निर्देश देना निश्चित रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है,लेकिन व्यवस्था में वास्तविक सुधार तभी दिखाई देगा,जब निरीक्षण के साथ पिछली अनियमितताओं की समीक्षा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, शासन और प्रशासन को यह संदेश देना होगा कि धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है,यह संदेश केवल नई खरीदी के निर्देशों से नहीं,बल्कि पुराने मामलों में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई से जाएगा, यदि किसी कर्मचारी पर अनियमितता के आरोप हैं तो जांच के निष्कर्ष के आधार पर उसकी भूमिका तय होनी चाहिए,न तो किसी निर्दोष को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जाए और न ही किसी जिम्मेदार को केवल इसलिए बचने दिया जाए कि नया खरीदी सत्र शुरू हो चुका है,आज जिले के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार धान खरीदी व्यवस्था वास्तव में बदलेगी या फिर केवल कैलेंडर बदलेगा और पुरानी कार्यप्रणाली नए सत्र में भी जारी रहेगी? किसानों को सुविधाएं देना जरूरी है,लेकिन उन सुविधाओं के साथ ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था देना उससे भी अधिक जरूरी है,नई धान खरीदी शुरू हो चुकी है,केंद्रों में निरीक्षण भी हो रहे हैं और पारदर्शिता के दावे भी किए जा रहे हैं,लेकिन जब तक पिछले सत्र की शिकायतों,अनियमितताओं और कार्रवाई का हिसाब सामने नहीं आएगा,तब तक एक सवाल बना रहेगा–क्या व्यवस्था सचमुच सुधरी है या पुरानी गड़बड़ियों पर पर्दा डालकर केवल नया सत्र शुरू कर दिया गया है? क्योंकि किसानों का भरोसा केवल निर्देशों से नहीं,निष्पक्ष जांच, पारदर्शी खरीदी और दोषी पाए जाने वालों पर ठोस कार्रवाई से जीता जा सकता है।

किसानों से संवाद,लेकिन व्यवस्था पर उठे पुराने सवालों का जवाब कौन देगा?

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से सीधे बातचीत कर खरीदी प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली,कृष्णपुर केंद्र में धान विक्रय करने पहुंचे किसान हेमसाय राजवाड़े ने बताया कि वे 54 क्विंटल धान बेचने आए हैं,वहीं नारायणपुर के किसान रामनरेश ने 100 क्विंटल धान का विक्रय किया,चंदरपुर समिति में भैयालाल,हंसलाल और रामजतन साहू सहित कुल 19 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा, कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता राशि की जानकारी भी ली,संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और गांव-गांव में मुनादी के माध्यम से किसानों को जानकारी देने के निर्देश दिए,उन्होंने स्वयं मोबाइल के माध्यम से'तुंहर हाथ'टोकन एप पर टोकन काटने की प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा किसानों को डिजिटल माध्यम से टोकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा,किसानों से संवाद और डिजिटल टोकन व्यवस्था का निरीक्षण प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है,मगर किसानों की परेशानी केवल टोकन मिलने या केंद्र में बैठने की जगह उपलब्ध होने तक सीमित नहीं होती,किसान चाहता है कि उसकी उपज का सही वजन हो,गुणवत्ता के नाम पर अनावश्यक परेशानी न हो,भुगतान समय पर मिले और खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की अनियमितता न हो,इसके लिए जरूरी है कि खरीदी व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो,ऐसे में प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि पिछली खरीदी में सामने आई शिकायतों पर क्या निष्कर्ष निकला,क्या किसी समिति में रिकॉर्ड की जांच हुई? क्या धान की कमी या अन्य अनियमितताओं के मामलों में जिम्मेदारों की पहचान की गई? क्या किसी से वसूली की गई? क्या किसी कर्मचारी को खरीदी कार्य से हटाया गया? यदि कार्रवाई हुई है तो उसका विवरण सामने आना चाहिए, ताकि किसानों को यह भरोसा हो सके कि व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई संरक्षण नहीं है।







60 केंद्रों में 68,531 किसानों से खरीदी,छह नए केंद्र भी शुरू

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के 60 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 68,531 पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी,किसानों की सुविधा और उपार्जन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में छह नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं,खरीदी के शुरुआती दो दिनों में जिले के 35 धान उपार्जन केंद्रों में 300 किसानों से कुल 12,408 क्विंटल धान खरीदे जाने की जानकारी दी गई है,यह आंकड़ा बताता है कि खरीदी प्रक्रिया शुरू होते ही केंद्रों में किसानों की आवक प्रारंभ हो गई है, आने वाले दिनों में खरीदी का दबाव बढ़ने के साथ केंद्रों की व्यवस्थाओं की वास्तविक परीक्षा भी होगी,जिले में 68 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों की उपज की खरीदी होना एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है,इतने बड़े स्तर पर खरीदी में छोटी-सी लापरवाही भी किसानों को प्रभावित कर सकती है,इसलिए केवल शुरुआती दिनों में निरीक्षण कर लेना पर्याप्त नहीं होगा,खरीदी के अंतिम दिन तक केंद्रों की निगरानी,रिकॉर्ड का सत्यापन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी होगी,लेकिन इस पूरी व्यवस्था के साथ एक पुराना सवाल भी जुड़ा है—क्या इस बार उन्हीं कमियों को दोहराने से बचने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई गई है,जिनके कारण पिछले सत्र में शिकायतें सामने आई थीं? यदि पिछली गड़बड़ियों की जांच और कार्रवाई का परिणाम सामने नहीं आएगा, तो नई व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

डीईओ ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण,अनुपस्थित प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक पर गिरेगी गाज

-संवाददाता-

बलरामपुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और स्कूलों में शिक्षकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एन.के.निरापुरे एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने मंगलवार को जिले के कई विद्यालयों का औचक दौरा कर पढ़ाई के स्तर,पाठ्यक्रम की स्थिति और स्टाफ की मौजूदगी की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला पण्डोपारा में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्रधान पाठक सुदेश्वर समट और सहायक शिक्षक गणेश राम राठिया बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी से नदारद मिले। डीईओ ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं,प्राथमिक शाला गौरापारा, चम्पापुर, कोदाकी और चन्दोरा में व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलीं और सभी शिक्षक अपने कर्तव्य पर उपस्थित पाए गए। इसके अलावा,हाई स्कूल भेंडरी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टाफ को तय समय-सीमा के भीतर सिलेबस पूरा कराने की हिदायत दी।

धान खरीदी केंद्र का भी लिया जायजा : स्कूलों के अलावा, कलेक्टर के आदेशानुसार डीईओ निरापुरे ने रनहत स्थित धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने उपार्जन व्यवस्था का अवलोकन करते हुए कर्मचारियों को शासन के तय मानकों के अनुसार ही धान खरीदी करने और केंद्र में आने वाले किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। दौरे में उन्होंने दो टूक कहा कि अध्यापन कार्य और समय की पाबंदी में किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।





SECL का कैसा आर्थिक गणित? उत्पादन करती खदान बंद की...अब उसी को चालू करने के लिए नया निवेश!

चलती खदान पर 2017 में लगाया ताला,अब करोड़ों खर्च कर फिर खोलने की तैयारी!

पहले चालू खदान बंद की,मशीनें चोरों के हवाले कीं,अब दोबारा शुरू करने में जुटा SECL प्रबंधन!

SECL का कैसा आर्थिक गणित? उत्पादन करती खदान बंद की,अब उसी को चालू करने के लिए नया निवेश!

नौ साल पहले क्यों बंद की कटकोना 3×4 अब उसी खदान में सीएम मशीन लगाने की तैयारी,पुराने फैसले पर सवाल...

खदान बंद कर छोड़े करोड़ों के उपकरण, चोरी से हुआ नुकसान,अब उसी खदान को फिर शुरू करने की कवायद!

जब कोयला उत्पादन हो रहा था तो खदान बंद क्यों की? अब उसी कटकोना 3×4 पर फिर करोड़ों लगाने की तैयारी!

एसडीएल मशीन से चल रही खदान बंद,अब सीएम मशीन से दोबारा उत्पादन की तैयारी,SECL के फैसलों का हिसाब कौन देगा?

पहले खदान बंद करने का फैसला, अब दोबारा खोलने की मशक्कत, SECL की नौ साल की...

चलती खदान पर SECL ने लगाया ताला,मशीनें हुई असुरक्षित,अब करोड़ों खर्च कर फिर खोलने की तैयारी!

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी उपक्रमों में योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों के हाथों में होती है,जिनसे सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और दूरदर्शी निर्णय की अपेक्षा की जाती है,लेकिन जब किसी चालू खदान को कोयला उत्पादन के दौरान ही बंद कर दिया जाए, उसके भीतर मौजूद करोड़ों रुपये की मशीनरी और पूरा अधोसंरचना तंत्र असुरक्षित छोड़ दिया जाए और वर्षों बाद उसी खदान को दोबारा शुरू करने के लिए नई मशीनों तथा तकनीक पर निवेश करना पड़े,तब प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र की कटकोना 3×4 खदान का मामला कुछ ऐसा ही है,वर्ष 2017 में इस खदान को उस समय बंद करने का निर्णय लिया गया,जब वहां कोयला उत्पादन हो रहा था,खदान के भीतर उत्पादन से जुड़ा पूरा सेटअप मौजूद था,एसडीएल मशीन के माध्यम से कोयला निकाला जा रहा था और खदान संचालन की स्थिति में थी,स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार खदान में उपलब्ध कोयला भंडार का बड़ा हिस्सा अभी निकाला जाना बाकी था,बताया जाता है कि निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का 60 प्रतिशत भी हासिल नहीं हो पाया था,इसके बावजूद प्रबंधन ने आर्थिक नुकसान और मुनाफे का हवाला देते हुए खदान बंद करने का निर्णय ले लिया,आज लगभग नौ वर्ष बाद उसी कटकोना 3/4 खदान को फिर से शुरू करने की पहल हो रही है,अब पुरानी एसडीएल मशीन के स्थान पर आधुनिक सीएम मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है। खदान तक पहुंचने वाली सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर भूमिगत कार्यों और मैन राइडिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं के लिए नए टेंडर और निर्माण कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि 2017 में खदान बंद करना आर्थिक रूप से सही निर्णय था तो आज उसे दोबारा शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और यदि आज उसी खदान में कोयला उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं दिखाई दे रही हैं तो क्या वर्ष 2017 में खदान को बंद करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था? क्या उस समय उत्पादन बढ़ाने, मशीनरी का आधुनिकीकरण करने और खदान के विकास के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया गया था?

चलती खदान को बंद करने का फैसला, आखिर किस आधार पर?- कटकोना 3×4 खदान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बंद करते समय खदान पूरी तरह अनुपयोगी अथवा उत्पादनविहीन नहीं थी, वहां कोयला उत्पादन जारी था,एसडीएल मशीन से कोयला निकाला जा रहा था और भूमिगत खदान का संचालन करने के लिए आवश्यक संरचनाएं एवं उपकरण मौजूद थे,खदान प्रबंधन के सामने यदि उत्पादन लागत और मुनाफे का सवाल था तो उसका समाधान उत्पादन क्षमता बढ़ाने,नई तकनीक अपनाने,मशीनरी के आधुनिकीकरण और खनन क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से भी तलाशा जा सकता था,लेकिन प्रबंधन ने खदान को बंद करने का रास्ता चुना, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खदान के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का 60 प्रतिशत भी हासिल नहीं हुआ था,तब उसकी वास्तविक उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किए बिना उसे बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या खदान की आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन केवल तत्कालीन उत्पादन और लागत के आधार पर किया गया था? क्या भविष्य में उपलब्ध कोयला भंडार और नई तकनीक के उपयोग से उत्पादन बढ़ने की संभावनाओं का आकलन किया गया था? यदि खदान में कोयला भंडार पर्याप्त था और उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश थी तो क्या उसे बंद करने के बजाय चरणबद्ध विकास की योजना नहीं बनाई जा सकती थी? इन सवालों का जवाब उस समय खदान बंद करने का प्रस्ताव तैयार करने वाले अधिकारियों और उसे स्वीकृति देने वाले प्रबंधन से मांगा जाना चाहिए।

करोड़ों के उपकरण खदान के अंदर छोड़ दिए,दूसरी खदानों में भी नहीं किया उपयोग- इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू खदान बंद होने के बाद वहां मौजूद मशीनरी और उपकरणों का है, खदान के भीतर उत्पादन से संबंधित कई उपकरण और संसाधन मौजूद थे,इन्हें सुरक्षित निकालकर दूसरी खदानों में उपयोग करने की संभावना भी थी,लेकिन जानकारी के अनुसार खदान बंद करने के बाद सभी उपकरणों को वहां से नहीं निकाला जा सका, कुछ संसाधन खदान के अंदर और आसपास ही रह गए। खदान बंद होने के बाद उनका नियमित उपयोग बंद हो गया और सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ कर्मचारियों को सौंप दी गई, यहां सवाल उठता है कि जब कंपनी की एक खदान बंद हो रही थी और दूसरी खदानों में मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता थी तो वहां उपलब्ध संसाधनों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना क्यों नहीं बनाई गई? क्या उस समय उपकरणों की सूची तैयार की गई थी? कितने उपकरण उपयोग योग्य थे? कितने उपकरण दूसरी खदानों में भेजे गए और कितने वहीं छोड़ दिए गए? क्या उनकी तकनीकी स्थिति का परीक्षण किया गया था? यदि खदान के भीतर मौजूद उपकरणों को समय रहते निकाल लिया जाता तो कंपनी को दूसरी खदानों में उनका उपयोग करने का अवसर मिल सकता था, इससे नए उपकरण खरीदने और संसाधनों पर दोबारा निवेश करने का आर्थिक बोझ भी कम हो सकता था,लेकिन यदि करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को बिना समुचित उपयोग योजना के बंद खदान में छोड़ दिया गया तो यह प्रबंधन की गंभीर चूक का विषय है।

खदान बंद हुई तो चोरों के निशाने पर आए सरकारी उपकरण-खदान बंद होने के बाद वहां मौजूद मशीनरी और उपकरणों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई, स्थानीय स्तर पर यह आरोप सामने आए हैं कि बंद खदान में मौजूद कई उपकरणों को चोरों ने निशाना बनाया और धीरे-धीरे संसाधनों को नुकसान पहुंचाया, स्थिति इतनी गंभीर बताई जाती है कि खदान की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को भी कई बार चोरों के विरोध और हमले का सामना करना पड़ा,आरोप है कि सुरक्षा में लगे कुछ कर्मचारियों की पिटाई तक की गई,यह स्थिति अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस कंपनी के पास सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारी,कर्मचारी और प्रशासनिक तंत्र मौजूद है,वहां सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को ही असुरक्षित परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा? क्या खदान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे? क्या सीआईएसएफ अथवा कंपनी की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुनिश्चित की गई थी? क्या चोरी की घटनाओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई? क्या चोरी गए उपकरणों की कीमत का आकलन किया गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया? यदि बंद खदान की सुरक्षा में लगे कर्मचारी बार-बार हमलों का सामना कर रहे थे तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए गए? खदान बंद करना एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता है,लेकिन उसके भीतर मौजूद सरकारी मशीनरी और संसाधनों को असुरक्षित छोड़ना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

पहले बंद करो,फिर नई मशीन खरीदकर दोबारा शुरू करो,यह कैसा आर्थिक गणित?- कटकोना 3×4 का मामला एसईसीएल की आर्थिक निर्णय प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है,वर्ष 2017 में खदान को नुकसान का हवाला देकर बंद किया गया, उस समय खदान में मशीनरी मौजूद थी, कर्मचारी काम कर रहे थे और उत्पादन भी जारी था, इसके बाद खदान बंद हुई,कर्मचारी दूसरे क्षेत्रों में भेज दिए गए और कुछ कर्मचारियों को वहां मौजूद संसाधनों की सुरक्षा में लगा दिया गया, अब वर्षों बाद उसी खदान को फिर से शुरू करने के लिए नई मशीनों,सड़क चौड़ीकरण,मैन राइडिंग सिस्टम और अन्य अधोसंरचना पर निवेश की तैयारी है,यानी पहले से तैयार खदान को बंद करने के बाद अब उसे दोबारा उत्पादन योग्य बनाने के लिए नए सिरे से संसाधन लगाने पड़ रहे हैं,यहां सवाल यह है कि 2017 में खदान को बंद करने से कंपनी को कितना आर्थिक लाभ हुआ? उस समय खदान में मौजूद मशीनरी की कुल कीमत कितनी थी? बंदी के बाद कितने उपकरण सुरक्षित रहे? कितने उपकरण चोरी हुए या अनुपयोगी हो गए? अब पुनः संचालन के लिए कुल कितना निवेश प्रस्तावित है? यदि बंदी के समय मौजूद संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया और अब नई मशीनरी तथा अधोसंरचना पर करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं तो उस पुराने निर्णय का आर्थिक ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? कंपनी को यह भी बताना चाहिए कि खदान बंद करने से लेकर पुनः शुरू करने तक कुल कितना खर्च हुआ और इस पूरी अवधि में उपलब्ध कोयला भंडार का कितना हिस्सा अप्रयुक्त पड़ा रहा।

अब सीएम मशीन से उत्पादन की उम्मीद, लेकिन पुराने फैसले का हिसाब कौन देगा?- कटकोना 3×4 को दोबारा शुरू करने की पहल से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी को अब भी इस क्षेत्र में कोयला उत्पादन की संभावना दिखाई दे रही है,नई तकनीक और आधुनिक मशीनरी के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की जा रही है,लेकिन नई मशीन लगाने से पुराने फैसले का सवाल खत्म नहीं हो जाता,बल्कि अब यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आज इसी खदान में उत्पादन की संभावना देखी जा रही है तो वर्ष 2017 में इसे बंद करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया था,क्या उस समय खदान के आर्थिक मॉडल का गलत आकलन हुआ था? क्या नई मशीनरी लगाने की संभावना पर विचार नहीं किया गया? क्या उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त समय और निवेश उपलब्ध कराया गया था? यदि आज सीएम मशीन लगाकर उसी खदान से कोयला निकालना आर्थिक रूप से उचित माना जा रहा है तो पुराने निर्णय की समीक्षा जरूरी है।

कटकोना 3×4 की बंदी और पुनः शुरुआत के पूरे मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रबंधन को स्पष्ट जवाब देना चाहिए...

1. वर्ष 2017 में खदान बंद करने का वास्तविक कारण क्या था? क्या केवल आर्थिक नुकसान इसका आधार था?
2. खदान बंद करते समय वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना था और वास्तविक उत्पादन कितना हो रहा था?
3. खदान के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का 60 प्रतिशत भी हासिल नहीं होने के बावजूद उसे बंद क्यों किया गया?
4. उस समय खदान के अंदर कितनी एसडीएल मशीनें और अन्य उपकरण मौजूद थे?
5. बंदी के बाद कितने उपकरण सुरक्षित निकाले गए और कितने खदान के अंदर छोड़ दिए गए?
6. बंद खदान में मौजूद मशीनरी और संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या है?
7. चोरी की घटनाओं में कितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ और कितनी एफआईआर दर्ज कराई गई?
8. सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों पर हमले की घटनाओं की जांच हुई या नहीं?
9. खदान को फिर से शुरू करने के लिए कितने करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है?
10. पुरानी मशीनरी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सका और अब सीएम मशीन लगाने का निर्णय किन तकनीकी आधारों पर लिया गया?
11. वर्ष 2017 में खदान बंद करने के निर्णय का कोई स्वतंत्र आर्थिक और तकनीकी ऑडिट कराया गया है या नहीं?

यह केवल खदान बंद करने का मामला नहीं,सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग का सवाल है-एसईसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है और देश के सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, यहां होने वाला प्रत्येक आर्थिक निर्णय कंपनी के संसाधनों और सार्वजनिक धन से जुड़ा होता है, कटकोना 3/4 की कहानी में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस खदान में उत्पादन हो रहा था, उसे नुकसान के आधार पर बंद कर दिया गया,खदान में मौजूद मशीनरी और संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो सका। बंदी के बाद सुरक्षा संबंधी समस्याएं सामने आईं और अब उसी खदान को नई तकनीक के साथ फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है, यदि 2017 में खदान को बंद करने का फैसला सही था तो आज दोबारा शुरू करने के पीछे का आर्थिक औचित्य सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और यदि आज खदान में पर्याप्त उत्पादन की संभावना है तो पुराने निर्णय की समीक्षा कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि उस समय उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो खदान चल रही थी, जिसमें कोयला उत्पादन हो रहा था और जिसके अंदर पूरा सेटअप मौजूद था, उसे बंद करने का फैसला आखिर किसकी दूरदर्शिता का परिणाम था? आज उसी खदान को नई मशीनों से फिर शुरू करने के लिए करोड़ों का निवेश किया जा रहा है,यदि पुराने संसाधन सुरक्षित रहते और खदान को समय रहते विकसित किया जाता तो क्या कंपनी का नुकसान कम नहीं हो सकता था?

एसडीएल मशीन से हो रहा था उत्पादन, अब सीएम मशीन लगाने की तैयारी-

कटकोना 3/4 खदान में जब उत्पादन हो रहा था,तब एसडीएल मशीन के माध्यम से भूमिगत कोयला निकाला जाता था, अब खदान को दोबारा शुरू करने की योजना में आधुनिक सीएम यानी कंटीन्यूअस माइनर मशीन लगाने की तैयारी है।

वर्ष 2017 में बंदी के समय	अब पुनः शुरुआत की तैयारी
SDL मशीन से कोयला उत्पादन	CM मशीन लगाने की योजना
खदान में संचालन का सेटअप मौजूद	नई तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की तैयारी
भूमिगत संरचना पहले से उपलब्ध	आवश्यक अधोसंरचना का पुनर्विकास
कोयला उत्पादन जारी था	पुनः उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया

सीएम मशीन आधुनिक भूमिगत खनन तकनीक का हिस्सा है, जिसके माध्यम से कोयला निकालने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और उत्पादन क्षमता के अनुरूप बनाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जब आधुनिक तकनीक अपनाने की संभावना आज मौजूद है तो क्या वर्ष 2017 में भी खदान के आधुनिकीकरण का विकल्प नहीं था? क्या उस समय एसडीएल मशीन की जगह नई तकनीक अपनाकर खदान को आगे चलाया जा सकता था? क्या उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं होने का कारण मशीनों की क्षमता थी या फिर अन्य तकनीकी और आर्थिक समस्याएं थीं? यदि नई मशीन लगाने से आज खदान का संचालन आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है तो उस समय ऐसी संभावना का मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया?



60 प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य भी हासिल नहीं,फिर खदान बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी?

कटकोना 3/4 को लेकर एक और महत्वपूर्ण बिंदु उत्पादन लक्ष्य से जुड़ा है,स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार खदान निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का 60 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाई थी,यदि यह आंकड़ा सही है तो इसका अर्थ है कि खदान में उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश थी,ऐसे में प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं होने का वास्तविक कारण क्या था? क्या खदान की मशीनरी की क्षमता सीमित थी? क्या भूमिगत खनन क्षेत्र के विकास में देरी हो रही थी? क्या कर्मचारियों की कमी थी? क्या कोयले की गुणवत्ता और उत्पादन लागत का अंतर खदान को घाटे में ले जा रहा था? किसी भी खदान को आर्थिक रूप से नुकसानदायक घोषित करने से पहले उसके वर्तमान उत्पादन,भविष्य की संभावनाओं, उपलब्ध कोयला भंडार,तकनीकी सुधार और निवेश की लागत का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए, यदि उस समय खदान को बंद करने का निर्णय केवल तत्कालीन घाटे को देखते हुए लिया गया था और भविष्य की संभावनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया तो यह प्रबंधन की दूरदर्शिता पर बड़ा सवाल है।

सूरजपुर की सड़कें

दस साल पहले चौड़ी हुई सड़कें, अब अतिक्रमण ने फिर समेट दी चौड़ाई!

फुटपाथ से नाली तक कब्जा, सड़क पर सामान, निर्माण सामग्री और अधोषित ऑटो स्टैंड से बढ़ी जाम की समस्या



- कभी हुआ था विरोध, तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति ने कराया था चौड़ीकरण
- स्ट्रीट लाइट और चौड़ी सड़क से बढ़ी थी शहर की रौनक
- अब दुकानों का सामान, बोर्ड, निर्माण सामग्री और फुटपाथ पर कब्जे से सड़क हुई संकरी
- त्योहार, रैली और विसर्जन के समय बढ़ जाती है जाम की समस्या



विकास बनाम अतिक्रमण

अब नई सड़क नहीं, मौजूदा सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने की जरूरत

चौड़ी सड़क पर संकरा सफर,अतिक्रमण ने सूरजपुर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक!

सड़क चौड़ीकरण का लाभ अतिक्रमण की भेंट,फुटपाथ से नाली तक कब्जे!

दस साल में शहर बढ़ा,व्यापार बढ़ा,लेकिन सड़कों पर चलने की जगह घट गई!

कभी सड़क चौड़ीकरण का विरोध करने वाले आज उसी सड़क की उपयोगिता देख रहे,लेकिन दुकानों के बाहर कब्जे और निर्माण सामग्री ने शहर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक

तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति के कार्यकाल में बदली थी सूरजपुर की तस्वीर

अब चौड़ी सड़कों पर फुटपाथ से लेकर नालियों तक कब्जा,सड़क पर दुकान का सामान,निर्माण सामग्री और अधोषित ऑटो स्टैंड से बढ़ रही जाम की समस्या

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहरों का विकास केवल चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और चमचमाती स्ट्रीट लाइट से नहीं होता, बल्कि इन सुविधाओं को व्यवस्थित बनाए रखने की प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है,सूरजपुर शहर इसका एक उदाहरण बनता जा रहा है,लगभग दस वर्ष पहले शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था,उस समय इस कार्य का विरोध भी हुआ,लेकिन तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति ने शहर के भविष्य और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चौड़ीकरण का कार्य आगे बढ़ाया, परिणामस्वरूप शहर की तस्वीर बदली, आवागमन सुगम हुआ और व्यापारिक गतिविधियों को भी विस्तार मिला,लेकिन आज उसी चौड़ी सड़क की उपयोगिता पर अतिक्रमण ने सवाल खड़े कर दिए हैं,स्थिति यह है कि सड़कें कागजों और पुराने निर्माण के हिसाब से आज भी चौड़ी हैं,मगर जमीन पर दुकानों के बाहर फैला सामान,फुटपाथ पर कब्जे,नालियों के ऊपर रखी सामग्री,सड़क किनारे निर्माण कार्य और अव्यवस्थित पार्किंग ने उनकी उपयोगी चौड़ाई को लगातार समेटना शुरू कर दिया है,विडंबना देखिए,जिस सड़क को चौड़ा करने के लिए कभी प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा था,आज उसी सड़क को अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत महसूस हो रही है,अब शहरवासियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सूरजपुर को फिर सड़क चौड़ीकरण की जरूरत है या पहले से चौड़ी सड़कों को ही अतिक्रमण मुक्त कराने की जरूरत है?

विरोध के बीच हुआ था चौड़ीकरण, बदल गई थी शहर की तस्वीर-करीब एक दशक पहले सूरजपुर शहर की मुख्य सड़कें आज की तुलना में काफी संकरी थीं,बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के कारण यातायात की समस्या धीरे-धीरे गंभीर होती जा रही थी,इसी जरूरत को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण की पहल की गई,उस समय चौड़ीकरण को लेकर विरोध के स्वर भी उठे थे। कई लोगों को अपनी दुकानों और भवनों के सामने की जगह प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन प्रशासन ने शहर के दीर्घकालीन हित को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया, सड़क चौड़ीकरण के साथ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ने भी शहर को नया स्वरूप दिया, उस दौर में जो सड़कें लोगों को चौड़ी लगती थीं,आज उन्हीं सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के कारण जगह कम पड़ने लगी है,शहर का व्यापार बढ़ा, दुकानें बड़ी हुईं,भवनों का निर्माण हुआ और बाजार का विस्तार हुआ,लेकिन सार्वजनिक सड़क और फुटपाथ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पीछे छूटती दिखाई दे रही है।

फुटपाथ पर कब्जा,पैदल चलने वाले सड़क पर चलने को मजबूर-शहर में फुटपाथ की स्थिति भी चिंता का विषय बनती जा रही है,फुटपाथ का निर्माण पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इसका उपयोग दुकानों का सामान रखने,अस्थायी व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य निजी कार्यों के लिए होने लगा है,कहीं दुकान का सामान रखा है,कहीं ठेला लगा है तो कहीं निर्माण सामग्री ने रास्ता घेर रखा है,नतीजा यह है कि पैदल चलने वाले लोगों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर उतरना पड़ता है,इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है,बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है, बुजुर्ग,महिलाएं,बच्चे और दिव्यांगजन सबसे अधिक परेशानी झेलते हैं,विडंबना यह है कि पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई जगह पर कब्जा होने के बाद वही पैदल यात्री सड़क पर चलने लगते हैं और फिर सड़क पर यातायात बाधित होने की शिकायत सामने आती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि फुटपाथ आखिर किसके लिए बनाया गया था?

नाली भी नहीं बची,सड़क भी नहीं बची, फिर पानी निकासी और यातायात कैसे होगा?-अतिक्रमण की समस्या केवल सड़क और फुटपाथ तक सीमित नहीं है,कई स्थानों पर नालियों के ऊपर सामान रखने और उनके आसपास निर्माण सामग्री जमा करने से सफाई तथा जल निकासी में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है,नाली पर कब्जा होने से सफाई कर्मचारियों को भी परेशानी होती है,बरसात के दिनों में जल निकासी प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है,यदि सार्वजनिक नालियों को निजी उपयोग में ले लिया जाए तो इसका नुकसान पूरे मोहल्ले और आसपास के व्यापारिक क्षेत्र को उठाना पड़ता है,यहां भी वही सवाल है कि सार्वजनिक सुविधा का उपयोग निजी सुविधा के लिए कब तक होता रहेगा? सड़क,फुटपाथ और नाली तीनों का अपना अलग उद्देश्य है। यदि इन तीनों पर एक साथ कब्जे होने लगें तो शहर की व्यवस्था केवल कागजों में ही व्यवस्थित रह जाएगी।

मकान बनाना निजी जरूरत,लेकिन निर्माण सामग्री रखने के लिए सड़क ही क्यों?-शहर में मकान और दुकान निर्माण के दौरान सड़क किनारे रेत, गिट्टी,ईंट और अन्य निर्माण सामग्री जमा कर देने की समस्या भी सामने आती है,कई बार निर्माण कार्य कुछ दिनों में पूरा हो जाता है, लेकिन सामग्री लंबे समय तक सड़क के किनारे पड़ी रहती है,किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने या दुकान का विस्तार करने का पूरा अधिकार है,लेकिन इसके लिए सार्वजनिक सड़क को निर्माण स्थल बना देना उचित नहीं है,सवाल यह है कि निजी भवन निर्माण की लागत में सड़क और फुटपाथ को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा भी शामिल कर दी गई है क्या? निर्माण सामग्री सड़क पर रखे जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। रात के समय ऐसी सामग्री दुर्घटना का कारण भी बन सकती है, इसलिए नगर पालिका को निर्माण सामग्री सार्वजनिक मार्ग पर रखने के संबंध में स्पष्ट नियम लागू करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

त्योहार, रैली और विसर्जन के समय खुल जाती है व्यवस्था की पोल-सामान्य दिनों में किसी तरह चलने वाली यातायात व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उस समय सामने आती है जब शहर में धार्मिक जुलूस, विसर्जन, शोभायात्रा,राजनीतिक रैली और बड़े सामाजिक आयोजन होते हैं,ऐसे अवसरों पर शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों और वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है,पहले से अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण सीमित हो चुकी सड़क पर भीड़ बढ़ते ही जाम की स्थिति निर्मित होने लगती है,जिस सड़क को कभी इसी तरह की यातायात जरूरतों को देखते हुए चौड़ा किया गया था,वही सड़क अब भीड़ के समय संकरी महसूस होने लगती है,ऐसे में सवाल यह है कि क्या शहर को हर बड़े आयोजन के समय यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अलग से मशक्कत करनी पड़ेगी,या सामान्य दिनों में ही सड़क को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था बनाई जाएगी? यदि फुटपाथ खाली रहें,पार्किंग निर्धारित हो और सड़क किनारे अतिक्रमण न हो तो बड़े आयोजनों के समय भी यातायात संभालना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

करोड़ों की सड़क,लेकिन रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी?-सड़क चौड़ीकरण के पीछे सरकारी धन और प्रशासनिक प्रयास लगाए गए थे,इसका उद्देश्य केवल सड़क का निर्माण करना नहीं,बल्कि आने वाले वर्षों के लिए शहर की यातायात जरूरतों का समाधान करना था,लेकिन किसी भी विकास कार्य का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसके निर्माण के बाद भी उसकी उपयोगिता सुरक्षित रखी जाए,सड़क निर्माण के बाद अतिक्रमण रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नगर पालिका, यातायात विभाग,राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सड़क किनारे अतिक्रमण की नियमित निगरानी नहीं हो सकती? यदि कोई दुकानदार सार्वजनिक स्थान पर सामान रखता है,कोई व्यक्ति नाली पर कब्जा करता है या कोई भवन निर्माण कराने वाला सड़क पर सामग्री जमा करता है तो संबंधित विभागों को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए,अतिक्रमण को वर्षों तक बढ़ने देना और फिर समस्या गंभीर होने पर अभियान चलाना किसी स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकता।

कलेक्टर रेना जमील से शहरवासियों की उम्मीद, क्या शुरू होगा व्यवस्थित अतिक्रमण हटाओ अभियान?-सूरजपुर की यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की समस्या को लेकर अब शहरवासियों की निगाहें कलेक्टर रेना जमील पर टिकी हैं,लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन शहर के विकास और यातायात व्यवस्था को लेकर ठोस पहल करेगा, शहर की प्रमुख सड़कों, फुटपाथों और नालियों की वास्तविक स्थिति का सर्वे कराकर अतिक्रमण की पहचान की जा सकती है। इसके बाद नियमानुसार नोटिस जारी कर सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने की कार्रवाई की जा सकती है,इस अभियान में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए,छोटी दुकान हो या बड़ा प्रतिष्ठान,सार्वजनिक सड़क पर कब्जे के मामले में नियम समान रूप से लागू होने चाहिए,साथ ही वैध व्यावसायिक गतिविधियों और गरीब छोटे दुकानदारों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए जहां जरूरी हो,वहां नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए,शहरवासियों की अपेक्षा केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कुछ दिनों बाद फिर पुराने ढर्रे पर न लौट जाए।

नवागत एसडीएम प्रशांत कुशवाहा की जनसहयोग की अपील,अब पहल का इंतजार-इस संबंध में नवागत एसडीएम प्रशांत कुशवाहा ने कहा कि शहर को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाना सभी नगरवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है,प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की सहभागिता भी इसमें महत्वपूर्ण है। जनसहयोग से शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की जाएगी,उन्होंने शहरवासियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है,ताकि सामूहिक प्रयासों से सूरजपुर को स्वच्छ,सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाया जा सके,एसडीएम की यह अपील महत्वपूर्ण है,लेकिन इसके साथ प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्ययोजना भी जरूरी है,केवल जनसहयोग की अपील से सड़क और फुटपाथ खाली नहीं होंगे,इसके लिए अतिक्रमण की पहचान,स्पष्ट नियम,नियमित निगरानी और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है,व्यापारियों को भी यह समझना होगा कि सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके उनका व्यवसाय तो कुछ समय के लिए सुविधाजनक हो सकता है,लेकिन इससे पूरे शहर की व्यवस्था प्रभावित होती है।

अब नई सड़क नहीं, पुरानी सड़क की चौड़ाई वापस दिलाने की जरूरत-सूरजपुर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि शहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सड़क का निर्माण नहीं,बल्कि पहले से निर्मित सड़क की उपयोगिता को बचाए रखना है,करीब दस वर्ष पहले सड़क चौड़ीकरण का विरोध हुआ था, लेकिन समय ने उस निर्णय की उपयोगिता सामने रख दी,आज उसी सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है,अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह शहर की सड़कों को फिर से व्यवस्थित करे, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए खाली कराए, नालियों से कब्जे हटवाए,निर्माण सामग्री रखने के लिए नियम लागू करे और ऑटो तथा निजी वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाए, सूरजपुर को इस समय एक और चौड़ीकरण अभियान से ज्यादा अतिक्रमण मुक्त सड़क अभियान की जरूरत है,क्योंकि सड़क की चौड़ाई कम होने से ज्यादा चिंताजनक स्थिति तब होती है,जब चौड़ी सड़क होने के बावजूद आम आदमी को चलने की जगह न मिले,दस साल पहले सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन को विरोध झेलना पड़ा था,अब सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कितनी इच्छाशक्ति दिखाई जाती है,यही सूरजपुर के शहरी विकास की अगली परीक्षा होगी।

सड़क चौड़ी हुई या दुकानों के सामने निजी विस्तार का अवसर मिल गया?

सूरजपुर के व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानों के बाहर सामान रखने की प्रवृत्ति लगातार यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, कई स्थानों पर दुकान का सामान निर्धारित सीमा से बाहर निकालकर रखा जाता है,कहीं प्रचार बोर्ड सड़क तक पहुंच जाते हैं तो कहीं दुकानों के सामने अतिरिक्त सामग्री रखकर सार्वजनिक रास्ते को घेर लिया जाता है, व्यापारियों के लिए दुकान का विस्तार और सामान का प्रदर्शन व्यवसाय का हिस्सा हो सकता है,लेकिन सार्वजनिक फुटपाथ और सड़क किसी एक दुकान की निजी संपत्ति नहीं हैं,सवाल यह है कि क्या दुकान के भीतर की जगह कम पड़ने पर सड़क को अतिरिक्त गोदाम और फुटपाथ को निजी शोरूम बनाने की अनुमति मिल गई है? यदि हर दुकानदार अपनी सुविधा के हिसाब से सड़क का हिस्सा घेरने लगे तो फिर चौड़ीकरण का लाभ आखिर किसे मिलेगा? व्यापार बढ़ना शहर की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है,लेकिन व्यापार की सुविधा के नाम पर आम नागरिकों के आवागमन को बाधित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अधोषित ऑटो स्टैंड और अव्यवस्थित पार्किंग ने बढ़ाई परेशानी

शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारण सड़क किनारे ऑटो और अन्य यात्री वाहनों का खड़ा होना है,कई स्थानों पर निर्धारित पार्किंग अथवा स्टैंड की व्यवस्था के अभाव में वाहन सड़क किनारे ही सवारी बैठाते और उतारते दिखाई देते हैं, दुकानों के बाहर सामान,सड़क किनारे निर्माण सामग्री और उसी स्थान पर खड़े यात्री वाहन मिलकर आवागमन के लिए उपलब्ध जगह को और कम कर देते हैं, कई बार एक वाहन के रुकते ही पीछे वाहनों की कतार लग जाती है, व्यस्त समय में यह समस्या और गंभीर हो जाती है,यदि शहर में ऑटो स्टैंड और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान तय कर दिए जाएं तथा उनका पालन कराया जाए तो यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है,लेकिन केवल एक-दो दिन की कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए नियमित निगरानी जरूरी है।

खड़गवां में चिरमिरी-बिलासपुर-कोरबा सड़क किनारे पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई,जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से नदारद

आधीबार गांव के आसपास सड़क किनारे लगे हरे-भरे पेड़ों पर चल रही कुल्हाड़ी,विभागीय जमीन पर कटाई को लेकर उठे सवाल

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां (एमसीबी),17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

खड़गवां क्षेत्र के आधीबार गांव के आसपास चिरमिरी-बिलासपुर-कोरबा सड़क किनारे लगे हरे-भरे पेड़ों की कथित तौर पर धड़ल्ले से कटाई किए जाने का मामला सामने आया है, लोक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में लगे पेड़ों को दिनदहाड़े काटे जाने की शिकायतों ने विभागीय निगरानी और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं,ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सड़क किनारे लगे पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियां ले जाई जा रही हैं, लेकिन इस गतिविधि को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे लगे पेड़ों की कटाई का सिलसिला लगातार जारी है,पेड़ों को काटने वाले लोग दिन के उजाले में ही बेखौफ होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे लगे पेड़ सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में यदि इन्हें बिना अनुमति काटा जा रहा है तो यह गंभीर मामला है,सवाल यह भी है कि विभाग की जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई किसके आदेश से हो रही है और काटी गई लकड़ी आखिर कहां ले जाई जा रही है?

अधिकारी मुख्यालय से नदारद, निगरानी व्यवस्था पर सवाल- ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग खड़गवां के जिम्मेदार अधिकारी अक्सर मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहते,अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति के कारण क्षेत्र में विभागीय कार्यों और संपत्तियों की निगरानी प्रभावित हो रही है,इसी स्थिति का फायदा उठाकर सड़क किनारे लगे पेड़ों की कटाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है,हालांकि पेड़ों की कटाई किस व्यक्ति या समूह द्वारा की जा रही है और इसके पीछे



किसकी भूमिका है,यह जांच का विषय है,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सड़क सीमा में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है तो उसका आदेश कहां है? अनुमति नहीं दी गई है तो अब तक कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विभाग के पास सड़क किनारे लगे पेड़ों का कोई अभिलेख,गणना या निगरानी व्यवस्था है अथवा नहीं,यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

पर्यावरण को नुकसान,सड़क किनारे हरियाली पर संकट

सड़क किनारे लगे पेड़ केवल छाया देने का काम नहीं करते, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये पेड़ धूल और प्रदूषण को कम करने, तापमान नियंत्रित रखने तथा स्थानीय जैव विविधता को सहारा देने में मददगार होते हैं,ऐसे में यदि बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ों की कटाई होती है तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ सकता है,ग्रामीणों और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों ने चिंता जताई है कि इसी तरह पेड़ों की कटाई जारी रही तो आने वाले समय में सड़क किनारे हरियाली समाप्त होती जाएगी।

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग...

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि आधीबार गांव के आसपास चिरमिरी-बिलासपुर-कोरबा सड़क किनारे हुई पेड़ों की कटाई की तत्काल जांच कराई जाए। मौके का निरीक्षण कर यह पता लगाया जाए कि कितने पेड़ काटे गए,पेड़ किसकी अनुमति से काटे गए और लकड़ी कहां ले जाई गई,यदि कटाई अवैध पाई जाती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए,इसके साथ ही ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है,अब देखना होगा कि सड़क किनारे पेड़ों की कटाई के इस मामले में विभाग और जिला प्रशासन कब संज्ञान लेते हैं और हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।

CMYK

नौवारी साड़ी,घुंघरुओं की खनक और लावणी करती श्रद्धा कपूर के लाजवाब ठुमके,ईथा के गाने जी जी रे जी में दिखा एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज

श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का पहला गाना जी जी रे जी रिलीज हो गया है। अजय-अतुल के संगीत और श्रेया घोषाल की आवाज वाले इस गाने में श्रद्धा लावणी करती नजर आईं। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपने नए अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। उनकी आगामी फिल्म ईठा का पहला गानाजी जी रे जी रिलीज हो गया है। इस गाने में श्रद्धा लावणी करती नजर आ रही हैं। पारंपरिक मराठी परिधान,नथ,गहनों और घुंघरुओं के साथ अभिनेत्री ने अपने डांस से लोकनृत्य की खूबसूरती को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। अब पहला गाना रिलीज होने के साथ फिल्म की संगीत और नृत्य से जुड़ी दुनिया की झलक भी देखने को मिली है।

लावणी के रंग में नजर आई श्रद्धा कपूर

जी जी रे जी में श्रद्धा कपूर नौवारी साड़ी और पारंपरिक आभूषणों में नजर आ रही हैं। गाने में उनके डांस मूव्स के साथ चेहरे के हाव-भाव और लावणी की खास अदाएं भी देखने को मिलती हैं। इस प्रस्तुति को भव्य और प्रभावशाली बनाने के लिए पारंपरिक लावणी के साथ थिएटर परफॉर्मेंस का अंदाज भी जोड़ा गया है। गाने में श्रद्धा का किरदार ईठा एक कलाकार के रूप में अपनी पहचान और हुनर को सामने लाता है। यह ट्रैक फिल्म की कहानी के एक अहम पड़ाव की झलक भी पेश करता है। गाने को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है। इसे श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके



बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। गाने की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है। संगीत, गायकी और डांस का यह मेल फिल्म के माहौल को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता नजर आता है।

अजय-अतुल बोले... संगीत कहानी का हिस्सा होना चाहिए

अजय-अतुल के मुताबिक,ईथा जैसी फिल्म में संगीत केवल बैकग्राउंड तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे किरदार, कहानी और भावनाओं का हिस्सा बनना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईठा का व्यक्तित्व केवल मंच पर दिखाई देने वाली कलाकार तक सीमित नहीं है। उसके भीतर ताकत, गरिमा और संघर्ष की अपनी कहानी है। जी जी रे जी के जरिए उन्होंने लावणी की पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए इस कलाकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास को संगीत के माध्यम से पेश करने की कोशिश की है। संगीतकार जोड़ी ने अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल और श्रेया घोषाल की गायकी की भी तारीफ की। साथ ही श्रद्धा की मेहनत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लावणी की हर अदा को सही तरीके से पर्दे पर उतारने के लिए काफी प्रयास किया है।

श्रद्धा के लिए चुनौतीपूर्ण रहा लावणी करना

श्रद्धा कपूर ने बताया कि ईठा के किरदार में लावणी करना उनके लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा, हालांकि इसके साथ चुनौतियां भी थीं। उनके मुताबिक, लावणी की लय, भाव-भंगिमाएं और ऊर्जा इसे खास बनाती हैं। इस डांस फॉर्म को समझना और इसके जरिए एक दिग्गज कलाकार की दुनिया में प्रवेश करना उनके लिए नया अनुभव था। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक गाने में कलाकारों की मेहनत और इसके पीछे छिपी कहानी को महसूस कर पाएंगे।

वैभवी मर्चेंट ने बताई कोरियोग्राफी की सोच

कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने बताया कि गाने की प्रस्तुति तैयार करते समय कलाकार के मंच पर आने से पहले के संघर्ष और भावनाओं को ध्यान में रखा गया। उनके अनुसार, मंच पर पहुंचने के बाद कलाकार अपनी निजी परेशानियों को पीछे छोड़कर दर्शकों के साथ जुड़ जाता है। इसी विचार को डांस के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने श्रद्धा के समर्पण और मेहनत की तारीफ करते हुए निर्देशक लक्ष्मण उतेकर के साथ काम करने का अनुभव भी शानदार बताया। वहीं श्रेया घोषाल ने इस गाने को ऐसा अनुभव बताया,जिसमें उन्होंने सिर्फ इसे गाया नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए लावणी की भावना को जिया। उनके मुताबिक, अजय-अतुल की धुन में इस लोकनृत्य की ऊर्जा, चुलबुलापन और खूबसूरती मौजूद है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ईथा का निर्माण दिनेश विजान, लक्ष्मण उतेकर और करिश्मा शर्मा ने किया है। श्रद्धा कपूर अभिनीत यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



जैकी श्रॉफ ने मनाया कहीं प्यार ना हो जाए के 26 साल

साल 2000 में रिलीज हुई बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए ने अपनी रिलीज के 26 साल पूरे कर लिए हैं। मंगलवार को अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को फिर से दोहराया। अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें फिल्म के सभी कलाकार नजर आ रहे हैं। वीडियो पोस्ट कर लिखा,फिल्म कहीं प्यार न हो जाए ने अपनी रिलीज के 26 साल पूरे कर लिए हैं। के. मुरली मोहन राव के निर्देशन में बनी फिल्म के निर्माता नरेंद्र बजाज हैं। यह हॉलीवुड फिल्म द वेडिंग सिंगर-एडम सैंडलर और ड्रू बैरीमोर अभिनीत) का भारतीय रूपांतरण है। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया था और इसके गाने उस समय काफी लोकप्रिय हुए थे,खासकर इसका टाइटल ट्रैक कहीं प्यार ना हो जाए। फिल्म में सलमान खान,रानी मुखर्जी,रवीना टंडन,जैकी श्रॉफ,मोहनीश बहल और कश्मीरा शाह जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह सलमान खान और रवीना टंडन की एक साथ तीसरी और आखिरी फिल्म थी। फिल्म की कहानी प्रेम (सलमान खान) नाम के एक खुशमिजाज और प्रतिभाशाली गायक की है, जो शादियों और छोटे कार्यक्रमों में गाना गाता है। प्रेम निशा (रवीना टंडन) से प्यार करता है और दोनों की शादी होने वाली होती है लेकिन शादी के दिन निशा वहां नहीं आती और प्रेम को बताती है कि वह अमेरिका के एक अमीर लड़के से शादी कर रही है ताकि वह अपने बीमार भाई की देखभाल कर सके। निशा के इस धोखे से प्रेम पूरी तरह टूट जाता है और शराब पीने लगता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में प्रिया (रानी मुखर्जी) का आगमन होता है,जो धीरे-धीरे उसकी जिंदगी बदल देती है। 17 नवंबर 2000 को रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लागत के मुकाबले यह फिल्म अपनी कमाई निकालने में असफल रही और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित हुई थी।



फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ का धमाकेदार कमबैक,तेनु लेके जाना के टीजर देख बोले फैंस...हमारा हीरो वापस आ गया

मुंबई फायरिंग की घटना के करीब एक महीने बाद टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर वापसी की है। नए गाने तेनु लेके जाना का टीजर शेयर कर अभिनेता ने फैंस को खुश कर दिया बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के करीब एक महीने बाद अभिनेता ने सोशल मीडिया पर वापसी की है। सोमवार को उन्होंने अपने अपकमिंग गाने तेनु लेके जाना का टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद यह उनका पहला सोशल मीडिया पोस्ट है। इस वीडियो में टाइगर ब्लैक टक्सीडो में अपने शानदार लुक और फिट बॉडी को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ अभिनेत्री केतिका शर्मा भी दिखाई दे रही हैं। टाइगर की वापसी से उनके प्रशंसक काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक और चांस,एक और डांस,टाइगर ने खास अंदाज में की वापसी टाइगर श्रॉफ ने अपने नए गाने का टीजर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा,एक और चांस,एक और डांस। अभिनेता के इस छोटे से संदेश को उनकी वापसी का संकेत माना जा रहा है। वीडियो में वह ब्लैक टक्सीडो पहने नजर आते हैं। उनके शानदार डांस मूव्स और सिक्स पैक एब्स भी टीजर का खास आकर्षण हैं। गाने में टाइगर अभिनेत्री केतिका शर्मा के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे। टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने भी भाई की वापसी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे कमेंट में लिखा,वो वापस आ गया.वहीं,अभिनेता के फैंस भी उन्हें लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर देखकर उत्साहित नजर आए। एक यूजर ने लिखा,हमारा हीरो वापस आ गया।दूसरे ने कमेंट किया कि लंबे समय बाद टाइगर को अपनी फीड पर देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। एक अन्य फैन ने लिखा,टाइगर 2.0 वर्जन लोड हो गया है।

18 नवंबर को रिलीज होगा टाइगर का नया गाना

टाइगर श्रॉफ का गाना तेनु लेके जाना 18 नवंबर 2026 को टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज होने वाला है। यह साल 2009 में आई फिल्म जय वीरू के गाने तेनु ले का रीक्रिएटेड वर्जन है। ओरिजिनल गाने को ओमर इनायत ने अपनी आवाज दी थी। इसमें कुणाल खेमू और अंजना सुखानी नजर आए थे। अब नए वर्जन में टाइगर और केतिका शर्मा की जोड़ी दर्शकों का मनोरंजन करती दिखाई देगी।

जाह्नवी कपूर के साथ पुणे में की गाने की शूटिंग

सोशल मीडिया पर वापसी से पहले टाइगर अपने काम पर भी लौट चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक,अभिनेता ने हाल ही में पुणे में जाह्नवी कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म लग जा गले के लिए चार दिनों तक एक गाने की शूटिंग पूरी की है। यह शूट पुणे के कल्याणी नगर स्थित एक लोकप्रिय पब में हुआ। इस डांस नंबर को मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया है। शूटिंग के दौरान टाइगर ब्लॉन्ड हेयर लुक में नजर आए। बताया गया कि वह शॉर्ट्स के बीच डांसर्स और वहां मौजूद स्टाफ के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे।

फायरिंग के बाद टाइगर की सुरक्षा अब भी सख्त

काम पर वापसी के बावजूद टाइगर की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अभिनेता की टीम और उनके करीबियों से नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इसके तहत उन्हें टाइगर की लोकेशन और शूटिंग शेड्यूल से जुड़ी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है।

खेल-समाचार



टेस्ट सीरीज से पहले कीवी टीम को झटका

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले मेजबान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर और सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सैंटनर चोट के कारण पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सैंटनर के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ है,जिसके चलते वह भारत के खिलाफ दोनों टेस्ट मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार, 17 नवंबर को आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की। उनकी जगह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(1) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रवण कुमार आ0 / पति शंकर लाल जाति,निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-चर्च रोड़ केदारपुर, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1237/1, 1238 रकबा 0.07, 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 10.11.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(1) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रवण कुमार आ0 / पति शंकर लाल जाति निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-चर्च रोड़ केदारपुर, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1239, 1240/1 रकबा 0.08, 0.02 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक - 10.11.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

19 नवंबर से एशिया कप राइजिंग स्टार का आगाज

दोहा,17नवम्बर 2026। एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का आगाज 19 नवंबर से होने जा रहा है। भारत की ए टीम अपना पहला मैच नेपाल के खिलाफ 20 तारीख को खेलेगी,इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा,जो दोहा में होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबले की तैयारी हो चुकी है। कुछ ही दिन बाद दोनों टीमें एक दूसरे के सामने होंगी। होगा तो ये क्रिकेट का ही मैच,लेकिन खिलाड़ी कुछ जरूर बदल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया था। रविवार को फिर से महामुकाबले के लिए आप भी तैयार हो जाइए।

एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का आगाज 19 नवंबर से होगा

एसीसी की ओर से एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का आयोजन होना है। इसका पहला मैच 19 नवंबर यानी गुरुवार को खेला जाएगा। पहले दिन पहले मैच में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच मैच खेला जाएगा। इसी दिन दूसरा मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच



होना है। इस टूर्नामेंट की खास बात ये है कि कुछ टीमें तो पूरी मजबूती के साथ उतर रही हैं, वहीं कुछ टीमें ए को उतार रही हैं। भारत और पाकिस्तान की भी ए टीमें मैदान में उतरेंगी।

भारत की ए टीम

20 नवंबर को पहला मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगी

एशिया कप राइजिंग स्टार में भारत की ए टीम अपना पहला मैच खेलने के लिए 20 नवंबर यानी शुक्रवार को उतरेगी। उसका मैच नेपाल की टीम से होगा। इसी दिन पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। यहां टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी तिलक वर्मा निभाते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। टीम इंडिया ने दोहा में पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 22 नवंबर को खेला जाएगा दोहा में मुकाबला

इस बीच अगर भारत और पाकिस्तान के बीच के महामुकाबले की बात की जाए तो वो 22 नवंबर को खेला जाएगा। पहले नेपाल के खिलाफ खेलकर भारत का दूसरा मैच पाकिस्तान से होगा। ये मैच दोहा में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू होगा। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया ए टीम तिलक वर्मा (कप्तान),रिंकू सिंह (उप-कप्तान),अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी,प्रभसिमरन सिंह,कुमार कुशाग्र,सूर्यांश शेडगे,शाहबाज अहमद,विप्रज निगम,हर्ष दुबे,तनुश कोटियन,हर्षित राणा, प्रिंस यादव,अरशद खान,आयुष बडोनी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं पंखरासिया केरकेट्टा पति श्री सुनील केरकेट्टा,आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम माडो थाना आस्ता, तहसील मनौरा,जिला जशपुर छ. ग. । यह कि मैं वर्तमान में गोधनपुर,अम्बिकापुर में निवासरत हूँ। मेरे नाम पर आधार क्र. 3761 7074 2718 जारी है जिसमें मेरा नाम पंखरसिय केरकेट्टा दर्ज है, जब कि मेरा सही नाम पंखरासिया केरकेट्टा है,जो सही है, तथा मेरे शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित है। उक्त आधार कार्ड में मेरा जन्म तिथि 1-1-1971 दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही जन्म तिथि ।।-03-1971 है जो मेरे शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित है।

यह कि मेरे उक्त आधार कार्ड में मेरा सही नाम- पंखरासिया केरकेट्टा (PANKHRACIA KERKETTA) दर्ज कराने एवं मेरा सही जन्म तिथि 11-03-1971 दर्ज कराए जाने उपर्युक्त के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत है।

सपथकर्ता
पंखरासिया केरकेट्टा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं उर्मिला राजवाड़े पति स्व. विश्वनाथ राजवाड़े उम्र 37 वर्ष, निवासी नवाबांध पो. करजी थाना दरिमा जिला सरगुजा छ.ग. । कि मेरी पुत्री शिल्पा राजवाड़े के आनं-5271 0782 3824 है जिसमें मेरी पुत्री का नाम शिल्पा कुमारी तथा उसके पिता का नाम विश्वनाथ दर्ज है।

मेरी पुत्री का सही नाम शिल्पा राजवाड़े तथा उसके पिता का सही नाम स्व. विश्वनाथ राजवाडे है जो मेरी पुत्री के अंकसूची में दर्ज है। आधार कार्ड में अंकित मेरी पुत्री तथा उसके पिता के गलत नाम को सुधार कर मेरी पुत्री का सही नाम शिल्पा राजवाडे तथा उसके पिता का सही नाम स्व. विश्वनाथ राजवाड़े दर्ज किया जाये,जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही हूं।

सपथकर्ता
उर्मिला राजवाड़े

आरसीबी ने 5 खिलाड़ियों को किया रिलीज



नई दिल्ली,17 नवम्बर 2026। इंडियन प्रीमियर लीग 2027 की मिनी नीलामी से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है। लगातार दो बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार अपनी चैंपियन टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखने का फैसला किया है। हालांकि,फ्रेंचाइजी ने इंग्लैंड के युवा स्टार बल्लेबाज जैकब बेथेल सहित पांच खिलाड़ियों को रिलीज करके सभी को चौंका दिया है। रिलीज किए गए खिलाड़ियों में रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल और विहान मल्होत्रा भी शामिल हैं। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन कर लिया है। कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली भी आईपीएल 2027 में आरसीबी का हिस्सा बने रहेंगे।

जैकब बेथेल को रिलीज करके चौंकाया

आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट में सबसे बड़ा फैसला इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को रिलीज करना रहा है। बेथेल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिना जाता है। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजी का उन्हें रिलीज करना एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।बेथेल पिछले सीजन में आरसीबी की टीम का हिस्सा थे। हालांकि,आईपीएल 2027 से पहले टीम प्रबंधन ने उन्हें रिलीज कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बेथेल की घुटने की सर्जरी और उनकी उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी इस फैसले को प्रभावित किया हो सकता है। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने इसे रिलीज करने का आधिकारिक कारण नहीं बताया है।अब बेथेल नीलामी में शामिल होने की स्थिति में दूसरी फ्रेंचाइजियों के लिए विकल्प बन सकते हैं।

CMYK

छत्तीसगढ़ में आईएएस-आईपीएस का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा

अब 63% मिलेगा,जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी कैश दिया जाएगा

रायपुर,17 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में आईएएस,आईपीएस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। खास बात यह है कि जुलाई से अब तक की बकाया राशि का भुगतान भी कैश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी



की थी। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के महंगाई भत्ता नियम,1972 के तहत यह बढ़ी हुई दर राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू हो गई है।

अधिक भुगतान होने पर होगी वसूली

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि,यदि किसी अधिकारी को तय राशि से अधिक महंगाई भत्ते का भुगतान हो जाता है तो अतिरिक्त राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी। एरियर का भुगतान उसी कार्यालय से किया जाएगा,जहां से संबंधित अवधि में अधिकारी का वेतन निकाला गया था। संबंधित कार्यालयों को वेतन पर्चियों में संशोधन कर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भुगतान की गई राशि का समायोजन भी किया जाएगा।

विवादित वीडियो मामले में थाने पहुंचे अमित जोगी

रायपुर पुलिस ने दिया था दूसरा नोटिस,अपना बयान दर्ज कराएंगे

रायपुर,17 नवम्बर 2026। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी विवादित वीडियो पोस्ट करने के मामले में मंगलवार को रायपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर 'ज्ञानू-जानू की शादी' नाम से एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मिलते-जुलते दिखाए गए थे। जिस पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया था। इसके बाद अमित जोगी अपना पक्ष रखने थाने पहुंचे। दरअसल,अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर 'ज्ञानू-जानू की शादी' नाम से एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलते-जुलते मुखौटे पहने दो किरदार दिखाए गए थे। वीडियो में दोनों की प्रतीकात्मक शादी और हनीमून के दृश्य भी थे।



इसे कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक व्यंग्य के तौर पर बनाया गया था।

भाजपा नेताओं की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सिविल लाइन थाने पहुंचा था। नेताओं ने वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए अमित जोगी के खिलाफ शिकायत की और कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने अमित जोगी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196,352, 353(2),356(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया था।

विवाद बढ़ने पर पोस्ट हटाई,मांगी माफी

वीडियो को लेकर विवाद और आलोचना बढ़ने के बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दी थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद जताते हुए माना था कि अपनी बात रखने का तरीका उचित नहीं था। उन्होंने कहा था कि जिस मुद्दे को उठाना चाहते थे,उसे दूसरे तरीके से भी रखा जा सकता था।

शिक्षकों की पोस्टिंग में रिश्वतखोरी आरोपी टीचर की याचिका खारिज

बिलासपुर में मनवाही पोस्टिंग के नाम पर की थी अवैध वसूली,भ्रष्टाचार का चलेगा केस

बिलासपुर,17 नवम्बर 2026। हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने बिलासपुर में शिक्षक भर्ती के बाद मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी शिक्षक की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि,जांच में मिले सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सह आरोपी के बयान और खुद शिक्षक की ओर से एक लाख रुपए मिलने की बात स्वीकार किए जाने को हाईकोर्ट ने



आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार माना है। आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),बिलासपुर की ओर से 15 जुलाई 2022 को उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। दरअसल,सक्ती जिले के जैजैपुर स्थित ग्राम सोंठी के शिक्षक भूपेंद्र साहू ने 4 फरवरी 2022 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी ललिता साहू का चयन 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक के पद पर हुआ था। इसी दौरान बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू ने मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता के अनुसार,इसके लिए 52 हजार कैश और 33 हजार रुपए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दिए गए थे। जांच के दौरान नंदकुमार साहू का बयान दर्ज किया गया।

रायपुर में 1.27 करोड़ की ठगी का आरोपी कोर्ट में पेश...हथकड़ी में हंसता रहा दीपक टंडन,पुलिस ने मांगी 3 दिन की रिमांड

रायपुर,17 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की कथित ठगी के मामलों में घिरे होटल कारोबारी दीपक टंडन को रायपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। हथकड़ी पहने कोर्ट पहुंचे आरोपी के चेहरे पर शिकन की जगह मुस्कान नजर आई। पेशी के दौरान वह हंसता रहा और कैमरों की तरफ देखकर थम्स-अप का इशारा भी करता दिखा।

कोर्ट परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने नए ठगी मामले में पूछताछ के लिए आरोपी की तीन दिन की रिमांड मांगी है। दीपक टंडन पर करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी,ब्लैकमेलिंग और धमकी से जुड़े आरोप हैं। उसके खिलाफ रायपुर,बिलासपुर, सक्ती और कोरबा में अलग-अलग मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। रायपुर के तेलीबांधा थाने में आरोपी और उसकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हैं।

हथकड़ी में भी बेफिक्र दिखा आरोपी,कोर्ट में किया थम्स-अप

दीपक टंडन की कोर्ट में पेशी के दौरान उसका अलग ही अंदाज देखने को मिला। पुलिस की सुरक्षा के बीच हथकड़ी पहने आरोपी मुस्कुराता नजर आया। उसने मीडिया कैमरों की ओर देखकर थम्स-अप का इशारा भी किया। वहीं,किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।



SECL में ठेका दिलाने के नाम पर 56 लाख की ठगी का आरोप

दीपक टंडन के खिलाफ हाल ही में दर्ज आठवीं एफआईआर में SECL कोरबा में ठेका दिलाने के नाम पर दो लोगों से 56 लाख रुपए लेने का आरोप है। शिकायतकर्ता विकास कुमार नागले और श्याम सिंह ठाकुर के मुताबिक,आरोपी ने SECL में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती और कोल ट्रांसपोर्टिंग का ठेका दिलाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में सिक्योरिटी एजेंसी मैनेजर विकास कुमार नागले से 25 लाख और एजेंसी संचालक श्याम सिंह ठाकुर से 31 लाख रुपए लिए गए। आरोप है कि ठेका नहीं मिलने पर जब रकम वापस मांगी गई तो आरोपी टालमटोल करता रहा। रकम लौटाने के लिए दिए गए दोनों चेक बैंक में बाउंस हो गए। इसी शिकायत के आधार पर तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज किया गया है।

होटल वेलकम श्री पर कब्जा और धमकी का आरोप

रायपुर के वीआईपी रोड स्थित साधना मंडप (होटल वेलकम श्री) को लेकर सरिता वाजपेयी ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि लीज समाप्त होने के बाद भी दीपक टंडन ने होटल का कब्जा नहीं छोड़ा। इस मामले में नगर निगम की सील तोड़ने, जबरन प्रवेश,गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। इस प्रकरण में उसकी पत्नी बरखा टंडन का नाम भी आरोपी के रूप में सामने आया है।

जमीन और रेस्टोरेंट बेचने के नाम पर 36 लाख लेने का आरोप

शिकायतकर्ता आशीष जायसवाल के मुताबिक, दीपक टंडन ने करीब 16,500 वर्गफीट जमीन और एटमॉस्फिरिया रेस्टोरेंट बेचने का सौदा किया था। इस दौरान करीब 36 लाख रुपए लेने का आरोप है। शिकायत में कहा गया कि संबंधित जमीन दीपक और उसकी पत्नी बरखा टंडन के नाम पर नहीं थी।

फॉर्च्यूनर लीजेंडर के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी

आशीष जायसवाल की ही एक अन्य शिकायत में 2023 मॉडल टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए लेने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक, रकम लेने के बाद न तो गाड़ी दी गई और न ही पैसे वापस किए गए।

सरकारी कोयला टेंडर दिलाने के नाम पर 15 लाख की ठगी

सक्ती सिटी कोतवाली में किशन शर्मा की शिकायत पर भी मामला दर्ज है। आरोप है कि मार्च 2022 में दीपक टंडन ने बड़े अधिकारियों से पहचान होने का दावा करते हुए सरकारी कोयला टेंडर दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बदले 15 लाख रुपए लेने और गारंटी के तौर पर बंद बैंक खाते का चेक देने का आरोप है। बिलासपुर में एक मीडियाकर्मी की शिकायत पर भी दीपक टंडन के खिलाफ कार्रवाई हुई। आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार कर न्यूज पोर्टल तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए।

ग्रामीण ने डिप्टी रेंजर की वर्दी फाड़ी...थप्पड़ जड़ा,अवैध कटाई की जांच करने पहुंचे थे,विरोध कर पीटा,आरोपी बोला...और बनाओ वीडियो

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,17 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक डिप्टी रेंजर को पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार,डिप्टी रेंजर सूर्यकांत रात्रे अंधियारखोह परिसर में अवैध लकड़ी कटाई की जांच करने



पहुंचे थे,तभी वहां मौजूद शख्स ने जांच का विरोध किया और गाली-गलौज शुरू कर दी। मना करने पर आरोपी रुद्र प्रसाद मांझी (43) ने रेंजर को थप्पड़ मारा और वर्दी फाड़ दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। मारपीट में वन अधिकारी घायल हुए हैं। उनके गर्दन पर चोट आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है,इसलिए वह जांच का विरोध कर रहा था। जानकारी के अनुसार, घटना 24 अक्टूबर की है। डिप्टी रेंजर सूर्यकांत रात्रे अंधियारखोह परिसर में निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सेमरहा गांव में सेमल प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटाई की सूचना मिली। इसके बाद वे वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंचे। वहां जांच के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की कार्रवाई भी की गई।कार्रवाई पूरी करने के बाद जब डिप्टी रेंजर लौट रहे थे,तभी आरोपी रुद्र प्रसाद मांझी वहां पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक,आरोपी ने कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उसने सूर्यकांत रात्रे के साथ गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक अपशब्द कहे और उनका हाथ व गर्दन पकड़कर मारपीट की। इस दौरान अधिकारी की वर्दी के बटन टूट गए और गर्दन पर खरोंच आई। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

मेहनत को मिली पूंजी,छोटे कारोबारियों के सपनों को उड़ान दे रही पीएम स्वनिधि : अरुण साव

रायपुर,17 नवम्बर 2026। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों की मेहनत को पीएम स्वनिधि योजना ने पूंजी का सहारा दिया है। कभी साहूकारों का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाने वाली कमाई अब कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत बनें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें। एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा,तभी प्रदेश और देश विकसित होगा। उप मुख्यमंत्री साव ने आज बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव में योजना के हितग्राहियों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम में स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और इसके पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से व्यवसाय करने में सुविधा होगी। साव ने हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स भी वितरित किए। उन्होंने सफल पथ विक्रेताओं और उनके



प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित भी किया। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि छोटे व्यवसायियों का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा होता है। पहले कारोबार के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था। कोरोना काल में इन परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कठिनाइयों को समझा और वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध होने से लाखों पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार फिर खड़ा करने और आगे बढ़ाने का अवसर मिला। साव ने कहा कि योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने हितग्राहियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नियमित भुगतान कर अगले चरण का लाभ लें,आमदनी बढ़ाएं और बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ाएं। सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ें, ताकि पूरा परिवार सक्षम बने। उन्होंने डिजिटल लेन-देन अपनाने और पात्र हितग्राहियों के लिए उपलब्ध 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। साव ने कहा कि बिलासपुर लगातार उपलब्धियों के नए अध्याय जोड़ रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में बिलासपुर को देश में दूसरा तथा छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा को पहला स्थान मिला है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। अब पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को सम्मानित किया जाएगा।

एनएमडीसी की एल-1 और एल-2 भर्ती को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान...28 नवंबर को किरंदुल-बचेली परियोजना का होगा घेराव

दंतेवाड़ा,17 नवम्बर 2026। एनएमडीसी की एल-1 और एल-2 भर्ती को लेकर युवा बेरोजगार संघ और सर्व समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। भांसी में आयोजित बैठक में 28 नवंबर को एनएमडीसी की किरंदुल और बचेली परियोजनाओं का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कहा है कि भर्ती के मुद्दे को लेकर इससे पहले भी चार दिवसीय आंदोलन किया गया था। उस दौरान विधायक और सांसद के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात कर अपनी मांगें रखी थीं, लेकिन युवाओं के मुताबिक अब तक भर्ती



को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। इसी नाराजगी के चलते अब युवा बेरोजगार संघ और सर्व समाज ने दोबारा बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इस आंदोलन में दंतेवाड़ा,बीजापुर और सुकमा जिले के युवाओं के साथ सर्व समाज,व्यापारी संघ,ट्रक यूनियन,निजी कंपनियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ने की तैयारी है। आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि इस बार आंदोलन व्यापक स्तर पर होगा और मांग पूरी होने तक अनिश्चित कालीन धरना जारी रखने की चेतावनी दी है।

अवैध कॉस्मेटिक निर्माण फर्म पर छापा

5 लाख का सामान जब्त,बिना लाइसेंस बन रही थीं ब्यूटी क्रीम और सीरम

रायपुर,17 नवम्बर 2026। राजधानी रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बिना वैध लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। महावीर नगर स्थित



मेसर्स शिव बाबा इंटरनेशनल में औचक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से ब्यूटी क्रीम और फेशियल सीरम बनाए जाने का मामला सामने आया। टीम ने मौके से 12 प्रकार की मशीनें और 8 प्रकार के कच्चे माल सहित करीब 5 लाख रुपये की सामग्री जब्त की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश और सहायक औषधि नियंत्रक बेनी राम साहू के मार्गदर्शन में रायपुर की टीम ने यह कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान फर्म के संचालक महेंद्र सचदेव द्वारा बिना वैध कॉस्मेटिक्स निर्माण अनुज्ञप्ति के तीन प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने तीनों कॉस्मेटिक उत्पादों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण और विश्लेषण के लिए भेजे हैं। इसके अलावा निर्माण स्थल से उत्पाद बनाने में इस्तेमाल की जा रही 12 प्रकार की मशीनें और 8 प्रकार के कच्चे माल को भी जब्त किया गया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की है। अधिकारियों के मुताबिक,नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में औषधि नियंत्रण अधिकारी टेकचंद धीरहे,ईश्वरी नारायण सिंह,लक्ष्मी कौशिक और सुरेश साहू शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षक भी हड़ताल पर..सरकारी कार्यालय में काम प्रभावित,तहसीलों में अटके काम,लोग लगा रहे चक्कर

रायपुर,17 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब राजस्व विभाग के दूसरे कामों पर भी दिखने लगा है। पटवारियों के समर्थन और अपनी मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक (राजस्व निरीक्षक) भी मंगलवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राजस्व निरीक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाईं। वहीं तहसील कार्यालयों में काम कराने पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

तहसील पहुंच रहे लोग, नहीं हो रहे काम : रायपुर तहसील कार्यालय पहुंचे जितेंद्र शर्मा ने बताया कि,पटवारी और राजस्व निरीक्षक की हड़ताल से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तहसील पहुंचने पर कभी हड़ताल तो कभी बाबू नहीं होने और फाइल नहीं मिलने की बात कही जाती है। राजस्व मामलों में तारीख पर



तारीख मिल रही है। लोग अपना समय निकालकर कार्यालय पहुंचते हैं,लेकिन काम नहीं हो पाता।

रायगढ़ में पटवारियों के समर्थन में राजस्व निरीक्षक का प्रदर्शन : रायगढ़ में राजस्व निरीक्षकों ने पटवारियों की हड़ताल के समर्थन में एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और विरोध जताया। प्रदेशभर में राजस्व निरीक्षक जिला मुख्यालयों में जुटे, मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की।

पटवारियों के काम का अतिरिक्त बोझ मिलने से नाराज : राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हिस्से के कई काम राजस्व निरीक्षक को सौंपे जा रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे का अप्रूवल,पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल और आय,जाति व निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा पटवारियों के हल्कों का प्रभार देने और राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल जांच व रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। संघ का कहना है कि बिना अतिरिक्त संसाधन और व्यवस्था दिए काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है।

एक राजस्व निरीक्षक सर्किल में 3 से 100 गांवों की जिम्मेदारी : संघ के मुताबिक, एक राजस्व निरीक्षक सर्किल में 3 से लेकर 100 तक गांव आते हैं। प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं,जहां पद खाली होने के कारण दूसरे राजस्व निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। ऐसे में पहले से मौजूद जिम्मेदारियों के साथ पटवारियों का काम करना मुश्किल हो रहा है।

संसाधन भत्ता,पदोन्नति और खाली पद भरने की मांग...

राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर पहले भी शासन को कई बार ज्ञापन दिया गया है,लेकिन अब तक ठोस फैसला नहीं हुआ। संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय और जरूरी सामग्री,चैनमैन की व्यवस्था, वेतन विसंगति दूर करना,पदोन्नति और खाली पदों पर भर्ती शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के लिए मानदेय और विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी की गई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)